https://www.facebook.com/Kamal.Sandesh/ www.kamalsandesh.org @kamalsandeshbjp

कमल संदेश

भाजपा के नवनिर्मित केंद्रीय कार्यालय भवन का उद्घाटन

वर्ष-13, अंक-05 01-15 मार्च, 2018 (पाक्षिक) ₹20

कर्नाटकः दक्षिण में भाजपा का प्रवेश द्वार

'परिवर्तन के लिए संकल्पबद्ध है कर्नाटक की जनता'

'खेत खलिहान से गुजरता है देश की समृद्धि का रास्ता'

'बड़ी संख्या में निवेशकों की भागीदारी है परिवर्तन का संकेत'

माल्पे, उडुपी (कर्नाटक) में मछुआरा सम्मेलन को संबोधित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

जोवई और शिलांग (मेघालय) में आयोजित रैली में जनाभिवादन स्वीकार करते श्री अमित शाह

कटिपल्ला (कर्नाटक) में भाजपा कार्यकर्ता स्व. दीपक राव के घर पर उन्हें श्रद्धांजलि देते श्री अमित शाह

विवेकानंद इंस्टीट्यूशंस, पुत्तूर में छात्रों से संवाद करते श्री अमित शाह

कमल संदेश
पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक
संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य
सत्यपाल
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
मुकेश कुमार

संपर्क
फोन: +91(11) 23381428

फैक्स
फैक्स: +91(11) 23387887

ई-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

07 भ्रष्टाचार-मुक्त कर्नाटक के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं युवा: अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 20 फरवरी को पुत्तूर (दक्षिणी कन्नड़ जिला, कर्नाटक) स्थित विवेकानंद इंस्टीट्यूशंस में "न्यू इंडिया के निर्माण में युवाओं की भूमिका" विषय पर कॉलेज छात्रों को...

वैचारिकी
हमारे कार्य का आधार धर्म होना चाहिए 16

श्रद्धांजलि
लोकेंद्र सिंह चौहान / कल्याण सिंह चौहान 18

लेख
परीक्षा के लिए मोदी मंत्र 23

अन्य
'परिवर्तन के लिए संकल्पबद्ध है कर्नाटक की जनता' 09
भाजपा ने दिए 'भ्रष्टाचार-मुक्त' सरकार... 11
व्यावसायिक कोयले के खनन में निजी क्षेत्र का प्रवेश 13
'खेत खलिहान से गुजरता है देश की समृद्धि का रास्ता' 19
प्रधानमंत्री की फिलिस्तीन, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान की...20
बड़ी संख्या में निवेशकों की भागीदारी है परिवर्तन का संकेत:... 22
'जनता ने राज्य के विकास के लिए परिवर्तन करने का मन... 24
'कांग्रेस सरकार ने 10 वर्षों के कार्यकाल में भ्रष्टाचार करने के... 25
भाजपा के नवनिर्मित केंद्रीय कार्यालय भवन का उद्घाटन 26
करो अपने आप से स्पर्धा: नरेन्द्र मोदी 28
'किसानों की आय दोगुनी करने' पर राष्ट्रीय सम्मेलन 29
नीति आयोग के बजट आवंटन में 20 प्रतिशत की वृद्धि 30

स्थायी स्तंभ
सोशल मीडिया से 04
पत्र-पत्रिकाओं से 33
स्फुट विचार 33

संगठनात्मक गतिविधियां

10 भाजपा की शानदार जीत

गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर परचम लहराया। राज्य में भाजपा ने नगर निकाय...

12 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व बुनकर के प्रशिक्षण हेतु चिंतन बैठक संपन्न

भाजपा केंद्रीय कार्यालय में 9 फरवरी को...

सरकार की उपलब्धियां

14 रक्षा खरीद परिषद् ने 1850 करोड़ रुपये के बराबर की खरीद को मंजूरी दी

रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद् (डीएसी) ने 20 फरवरी...

15 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बजट आवंटन में 12.10 प्रतिशत की वृद्धि

वर्ष 2018-19 के लिए केंद्रीय बजट में...

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

twitter

@narendramodi

हमारी सभी सरकारें, चाहे केंद्र में हों या राज्यों में, वो रोजगार केन्द्रित होने के साथ ही जन केन्द्रित विकास पर जोर देती रही हैं।

@AmitShah

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार जिस तरह से काम कर रही है उससे देश के गरीबों और किसानों को आजादी के बाद पहली बार यह महसूस हो रहा है कि यह सरकार मेरी सरकार है।

@dpradhanbjp

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हमारे देश के युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा कर रही है तथा उनके लिए और अवसर पैदा कर रही है। मुद्रा ऋण ने 10 करोड़ से अधिक लोगों के व्यवसायों को बढ़ाया है और उनके सपनों को पूरा किया है।

facebook

अपनी रिपोर्ट में नीति आयोग ने छत्तीसगढ़ को 'अचीवर्स स्टेट' की सूची में देश के शीर्ष पांच राज्यों में रखा है। यह रिपोर्ट जनसेवा हेतु प्रतिबद्ध भाजपा सरकार के पिछले 14 वर्षों में स्वस्थ और खुशहाल छत्तीसगढ़ के निर्माण हेतु समर्पित होकर किए कार्यों का प्रतिफल है।

— **डॉ. रमन सिंह**

'मन की बात' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने झारखंड की महिलाओं की प्रशंसा की। स्वच्छ भारत अभियान को लेकर झारखंड की 15 लाख महिलाओं ने संगठित हो कर मात्र 20 दिन में ही एक लाख 70 हजार शौचालयों का निर्माण कर नई मिसाल कायम की है।

— **रघुबर दास**

राज्य के गरीब होनहार बच्चे अब प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने का सपना देख सकेंगे। इसके लिए उत्तराखंड सरकार, गेल(इण्डिया) व CSRL के बीच अल्मोड़ा एवं श्रीनगर में गेल उत्कर्ष सुपर 100 के दो केन्द्र स्थापित करने का समझौता हुआ है। इन केंद्रों में 100 मेधावी गरीब छात्रों को सरकारी खर्चे पर इंजीनियरिंग, आईटी, व अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षाओं की कोचिंग दी जाएगी।

— **त्रिवेंद्र सिंह रावत**

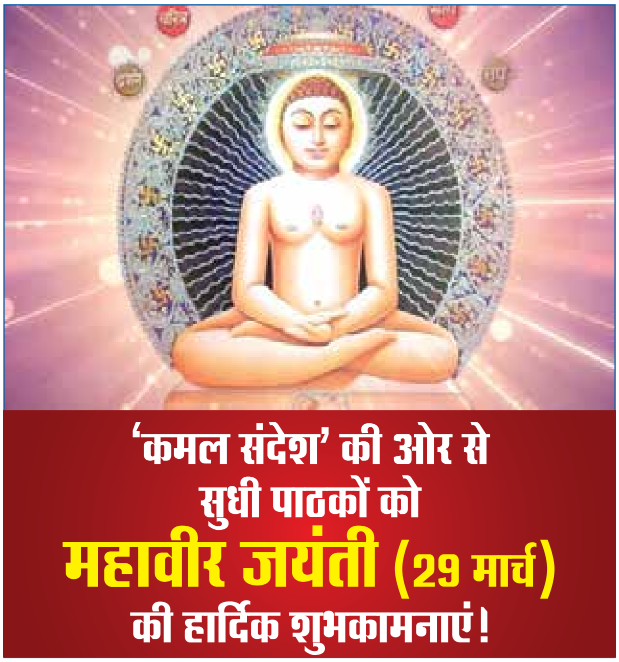

कांग्रेस यानी झूठ एवं फरेब की राजनीति

एक ओर मोदी सरकार का भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चल रहा है तब दूसरी ओर इसके फलस्वरूप कई घोटाले भी सामने आ रहे हैं। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि इन घोटालों की जड़ें कांग्रेस-नीत संप्रग के शासनकाल में हैं। कांग्रेस न केवल अपारदर्शी संस्कृति तथा गैर जिम्मेदाराना शासन के लिए जानी जाती है, बल्कि देश में भ्रष्टाचार एवं घोटालों को संरक्षण एवं सरपरस्ती भी देती रही है। इसके शासनकाल में जब भी भ्रष्टाचार के कारनामे बाहर आये, कांग्रेस ने शर्मनाक तरीके से इनपर कोई भी कार्रवाई करने से इन्कार कर दिया। देश अब भी यह भूला नहीं कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी कांग्रेस ने कालेधन पर एसआईटी गठित नहीं की तथा घोटालेबाजों एवं भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध हर कदम को रोकती रही। इतना ही नहीं, इसने भ्रष्टाचार रोकने के लिये न कभी कोई पहल की, न ही कोई कड़े कानून बनाये। पूरी व्यवस्था में इसने 'खुला खेल फर्रूखाबादी' के तर्ज पर भ्रष्टाचार की दीमक लगा दी। गरीब एवं वंचित के हिस्से का धन घोटाले एवं लूट की भेंट चढ़ता रहा तथा कांग्रेस हाथ पर हाथ धरे तमाशा देखती रही और इस लूट में भागीदार बनती रही। इससे देश को भारी क्षति पहुंची है।

यह केवल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का कालेधन, भ्रष्टाचार एवं घोटालों के विरुद्ध अथक प्रतिबद्धता का ही परिणाम है कि सरकार पर अब तक भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है। भ्रष्टाचार से बिना समझौता किये निरंतर युद्ध करने का ही परिणाम है कि देश आज पारदर्शी, जवाबदेह और साफ–सुथरी अर्थव्यवस्था के रूप में विश्व में अपना मुकाम बना रहा है।

भाजपा को किसी तरह से घेरने के चक्कर में कांग्रेस भाजपा सरकार पर हास्यास्पद आरोप लगा रही है। हाल ही में राहुल गांधी द्वारा राफेल समझौते पर अटपटे एवं आधारहीन प्रश्न उठाकर वे पुनः एक बार हंसी के पात्र बन गए हैं। कुछ दिन पूर्व उजागर हुआ पीएनबी घोटाले की भी जड़ें कांग्रेस शासन में ही पाई गई हैं, जब राष्ट्रीयकृत बैंकों से कई संदेहास्पद कर्ज दिये गये। इससे बैंकों का एनपीए इतना बढ़ गया कि पूरा बैंकिंग क्षेत्र संकटग्रस्त हो गया। इन सारे घपलों–घोटालों की जिम्मेदारी लेने के बजाय यह झूठ एवं फरेब की राजनीति के सहारे अपनी नैय्या पार लगाना चाहती है। कांग्रेस की लाचारी इस बात से समझी जा सकती है कि इसके दोनों शीर्ष नेतृत्व वर्तमान अध्यक्ष राहुल गांधी एवं पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड मामले पर जमानत पर हैं और अगस्टा–वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाले के नये–नये तार रोज सामने आ रहे हैं। कांग्रेस चाहती है कि इसके शासन काल के बड़े–बड़े घोटाले, जो लगभग 12 लाख करोड़ के थे, उसे जनता भूल जाये और इसके लिये वह लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। परन्तु वह यह भूल जाती है कि आधारहीन आरोपों से उसकी बची–खुची विश्वसनीयता भी खत्म हो रही है और देश की राजनीति में अब उसे कोई गंभीरता से नहीं ले रहा। ऐसा लगता है कि कांग्रेस नेतृत्व को अब भी यह भरोसा है कि वह झूठ एवं फरेब के दम पर फिर से देश की जनता को गुमराह कर सकती है।

मोदी सरकार भ्रष्टाचार, घोटाले एवं कालेधन के विरुद्ध अनवरत अभियान चला रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 'नोटबंदी' एवं 'जीएसटी' लागू करने की प्रबल राजनैतिक इच्छाशक्ति एवं साहस को जनता नमन कर रही है। इससे इनकी व्यवस्था में कांग्रेस द्वारा बोये भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने की संकल्पशक्ति परिलक्षित हुई है। अपने पहले ही कैबिनेट बैठक में कालेधन पर 'एसआईटी' गठित कर तथा काले धन को बैंकों में पनाह देने के लिये जाने वाले देश स्विट्जरलैंड से इस पर समझौते कर मोदी सरकार ने कालेधन पर शिकंजा कसने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। इसके साथ ही कड़े कानून बनाकर व्यवस्था की खामियों को दूर करने के गंभीर प्रयास हुए हैं। रियल–स्टेट, जो कालेधन का पनाहगार बन गया था तथा उपभोक्ताओं के साथ हेर–फेर में इसके कई लोग संलिप्त थे, अब 'रेरा' बन जाने से कानून का पालन करने पर मजबूर हैं। जनकल्याण कार्यों में भी 'डीबीटी' के माध्यम से सरकार ने जनता का भारी धन बचाया जा रहा है। यह केवल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का कालेधन, भ्रष्टाचार एवं घोटालों के विरुद्ध अथक प्रतिबद्धता का ही परिणाम है कि सरकार पर अब तक भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है। भ्रष्टाचार से बिना समझौता किये निरंतर युद्ध करने का ही परिणाम है कि देश आज पारदर्शी, जवाबदेह और साफ–सुथरी अर्थव्यवस्था के रूप में विश्व में अपना मुकाम बना रहा है। मोदी सरकार पर आधारहीन एवं बे–सिर–पैर के आरोप लगा कर कांग्रेस भ्रष्टाचार से अपने गठजोड़ को ही उजागर कर रही है। ■

shivshakti@kamalsandesh.org

कर्नाटक को 'मिशन सरकार' चाहिए, न कि 'कमीशन सरकार': नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मैसूर में 19 फरवरी को एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने सिद्धारमैया सरकार पर प्रहार करते हुए उपस्थित लोगों से पूछा- "आपको कर्नाटक में कैसी सरकार चाहिए? कमीशन लेने वाली या मिशन वाली। हमारी सरकार मिशन के लिए काम करती है। हमने कई काम मिशन के तौर पर किए है।"

श्री मोदी ने कहा कि आज मेरा सौभाग्य रहा कि मैसूर की धरती पर यहां के नागरिकों के लिए मुझे कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का लोकार्पण करने का अवसर मिला। मैसूर और बेंगलुरू के बीच रेलवे लाइन के बीच इलेक्ट्रिफिकेशन का लोकार्पण किया और मैसूर और उदयपुर के बीच हमसफर एक्सप्रेस को रवाना किया।

उन्होंने कहा, "हमने प्रधानमंत्री योजना के तहत देश के नौजवानों को ताकत दी। हमने 10 करोड़ का लोन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दिया है। करीब साढ़े चार लाख रुपया बैंक गारंटी के बिना नौजवानों के हाथ में दिया गया। 3 करोड़ से ज्यादा नए उद्यमी अपना काम शुरू कर रहे हैं। किसी ने एक को रोजगार दिया, किसी ने दो को रोजगार दिया। आज मेरे देश के नौजवान इस योजना के तहत स्वरोजगार करके सम्मान के साथ अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं, लेकिन कर्नाटक की सरकार को इसकी परवाह नहीं है। हमारा सपना है कि 2022 तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा ना हो, जिसके पास रहने के लिए अपना खुद का घर ना हो। हम 'ईज ऑफ लिविंग' पर बल दे रहे हैं। सरकार में नौजवानों को नौकरी देने के लिए इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू और वो भी वर्ग 3 और 4 के लिए। किसी परिवार में इंटरव्यू का कॉल आ जाए तो बिचौलिया आ जाता था। सिफारिश, खर्चे की बात करता था। मां बेचारी बेटे को नौकरी के लिए गहने-घर बेच देती थी। इंटरव्यू में 3 लोग बैठते थे और मुंडी देखते थे बस। कौन इतना बुद्धिमान है, जो शक्ल देखकर अच्छा-बुरा बता दे। ये पैसा कमाने का धंधा था कि नहीं? हमारी सरकार ने तय किया कि नौजवानों को तीसरी-चौथी श्रेणी में नौकरी चाहिए तो इंटरव्यू नहीं मेरिट के आधार पर मिलेगी। कर्नाटक सरकार को क्या तकलीफ है, लेकिन बिचौलियों को राजनीतिक हथियार बनाकर करोबार करते हैं।"

उन्होंने कहा, "अब कर्नाटक में गति की जरूरत है। कर्नाटक को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का वक्त इंतजार नहीं कर सकता है। आज केंद्र में एक ऐसी सरकार बैठी है, जो किसी भेदभाव के बिना हर राज्य को विकास के लिए बल देने के लिए प्रयास करती है। आप अगर गंगाजी में जाएं और इतना छोटा सा बर्तन लेकर जाएंगे और बड़ा बर्तन लेकर जाएंगे तो ज्यादा जल आएगा। कर्नाटक में छोटे मन के लोग बैठे हैं, जो डेढ़ बाई डेढ़ की कुर्सी की चिंता करते हैं, सैकड़ों किलोमीटर में फैले कर्नाटक की चिंता नहीं है।"

उन्होंने कहा, "मैंने बेंगलुरू में कहा था कि ये 10 फीसदी कमीशन का कारोबार है। मुझ पर सब लोग नाराज हो गए। कुछ लोगों ने मुझे फोन भी किया। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज भेजा और नाराजगी जाहिर की। उन्होंने मुझे कहा कि आपकी जानकारी सही नहीं है, ये 10 पर्सेंट नहीं, इससे भी ज्यादा वाले हैं। कर्नाटक के लोग मौजूदा सरकार को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आपको अब कर्नाटक में कमीशन वाली सरकार चाहिए या मिशन वाली सरकार चाहिए। कमीशन कि मिशन? मैं वादा करता हूं कि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनेगी और वो एक मिशन के तहत काम करेगी। कर्नाटक के भाग्य बदलने और विकास के लिए काम करेगी।"

उन्होंने कहा, "हर दिन नया भ्रष्टाचार होता है, हर दिन एक नेता पर आरोप लगता है। केंद्र सरकार जो पैसे दे रही है, उन पैसों का भी उपयोग कर्नाटक की सरकार नहीं कर पाती है। उसका कारण है। पहला उनकी ये प्राथमिकता ही नहीं है। उनके लिए दिल्ली को खुश रखना और उठापटक की राजनीति करना है। पार्टी के आकाओं को खुश रखना ही उनका कारोबार है। उन्हें कर्नाटक की परवाह नहीं है। वे अपने तरीके से, अपने हिसाब से अपने में ही खोये हुए हैं। ऐसी सरकार और ऐसा व्यक्ति कभी भी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था को ताकत नहीं दे सकता है।" ■

भ्रष्टाचार-मुक्त कर्नाटक के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं युवाः अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 20 फरवरी को पुत्तूर (दक्षिणी कन्नड़ जिला, कर्नाटक) स्थित विवेकानंद इंस्टीट्यूशंस में "न्यू इंडिया के निर्माण में युवाओं की भूमिका" विषय पर कॉलेज छात्रों को संबोधित किया और छात्रों से भारत की विकास यात्रा में अपनी भूमिका प्रभावी तरीके से निभाने का आह्वान किया।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपनी मातृभूमि और मातृभाषा से कट कर बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि मातृभाषा एवं मातृभूमि ही हमें अपनी जड़ों के साथ जोड़े रखती है, अपनी संस्कृति के साथ जोड़े रखती है और जीवन में आगे बढ़ने के लिये प्रेरित करती है। विवेकानंद इंस्टीट्यूशंस इसी विचार के साथ छात्रों को शिक्षा और संस्कार के साथ-साथ राष्ट्र के नव-निर्माण के लिए भी प्रेरित करती है, इसलिए यहां आकर मैं अपने-आप को काफी भाग्यशाली समझता हूं।

श्री शाह ने कहा कि देश में स्वराज की स्थापना के लिये आजादी के आंदोलन में न जाने कितने मनीषियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्होंने कहा कि स्वराज का मतलब केवल अपने लोगों के लिए चलाया जाने वाला शासन नहीं बल्कि देश के सर्वांगीण विकास व सबके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिये चलाया जाने वाला शासन है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पहले यूपीए के शासन में देश का भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा था, एक-के-बाद-एक 12 लाख करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के मामले देश की जनता के सामने आ रहे थे, सीमाओं की सुरक्षा खतरे में थी, महिलायें सुरक्षित नहीं थीं, युवा आक्रोशित थे और इस परिस्थिति में देश की जनता ने श्री नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुये भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण जनादेश दिया। उन्होंने कहा कि आगे जब भी देश का इतिहास लिखा जाएगा, 2014 का चुनाव स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा।

श्री शाह ने कहा, "प्रधानमंत्री बनते ही श्री नरेन्द्र भाई मोदी ने सरकार चलाने के लिये कुछ मूलभूत सिद्धांत तय किये - पहला यह कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में केवल सरकार चलाने के लिये नहीं है बल्कि देश को बदलने के लिये, देश को आगे बढ़ाने के लिये है। दूसरा सिद्धांत यह था कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार लोगों को अच्छे लगने वाले फैसले लेने की जगह ऐसे फैसले लेगी जोकि लोगों के लिये अच्छे हों और उनके जीवन स्तर में सुधार आ सके और तीसरा यह कि हम 'सबका साथ, सबका विकास' की अवधारणा पर आगे बढ़ेंगे।" उन्होंने कहा कि चार साल बाद मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मोदी सरकार ने इन तीनों सिद्धांतों को चरितार्थ करके दिखाया है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 2014 में जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार का गठन हुआ तब देश में 60% परिवार ऐसे थे, जिनके पास एक बैंक अकाउंट तक नहीं था, ग्रामीण क्षेत्रों में केवल एक करोड़ लोगों के पास ही एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध था, लगभग 18 हजार गांव ऐसे थे, जहां बिजली नहीं पहुंची थी, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के घरों में शौचालय नहीं था, आप कल्पना कर सकते हैं कि आजादी के इतने सालों बाद भी बुनियादी सुविधाएं लोगों को मयस्सर नहीं थी, किस प्रकार की सरकार कांग्रेस ने चलाई? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश के सर्वांगीण विकास के विजन पर देश में परिवर्तन लाने का बीड़ा उठाया और आज देश के लगभग हर परिवार के पास अपना बैंक अकाउंट है, लगभग साढ़े सात करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ है, हर स्कूल में छात्राओं के लिए शौचालयों का निर्माण किया गया है, 18 हजार गांवों में से 13 हजार गांवों में बिजली पहुंचाने का काम पूरा कर लिया गया है, साढ़े तीन करोड़ गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है और आयुष्मान भारत के अंतर्गत देश के लगभग 10 करोड़ परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा देने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश के सोचने के स्केल को ऊपर उठाने का काम किया है, उन्होंने रिफॉर्म्स की जगह ट्रांसफॉर्मेशन की

शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि देश का एक हिस्सा 21वीं शताब्दी में रहे और देश का गांव 18वीं शताब्दी में जीता रहे, इस तरह का विकास हमें नहीं चाहिए, पूरा देश 21वीं शताब्दी में जाना चाहिए, चाहे वह गांव का गरीब से गरीब घर हो या दिल्ली के लुटियन जोन में रहने वाला परिवार।

श्री शाह ने कहा कि देश की सुरक्षा के लिये भी मोदी सरकार ने कई कदम उठाये हैं। उन्होंने कहा कि पहले सीमा पार से होने वाले आतंकी हमलों के खिलाफ सरकार की कोई नीति ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और हमारे जवानों के अप्रतिम शौर्य के बल पर हमने 10 दिनों के अन्दर ही सर्जिकल स्ट्राइक कर के उरी हमले का बदला पाक प्रेरित आतंकवादियों से ले लिया। उन्होंने कहा कि इससे दुनिया में देश के प्रति देखने के नजरिये में बदलाव आया और दुनिया भर में संदेश गया कि हम सभी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं लेकिन अपनी सीमाओं के साथ खिलवाड़ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हमने अंतरिक्ष में एक साथ 104 उपग्रह प्रक्षेपित करके अमेरिका के रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया, इसे कहते हैं बदलते भारत की तस्वीर।

कर्नाटक के युवा आने वाले दिनों में कर्नाटक में एक ऐसी सरकार बनाएं जो कर्नाटक को आगे ले जाने का काम करे। विवेकानंद जी के आदर्शों पर चलते हुये "उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक कार्यरत रहो" के संकल्प के साथ हम अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ें। जब तक भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर पुनः प्रतिष्ठित नहीं होती, तब तक हम में से किसी को भी आराम करने का अधिकार नहीं है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने छात्रों का आह्वान करते हुए कहा कि मेहनत का कोई पर्याय नहीं होता और एक बड़े लक्ष्य को सामने रख कर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनवरत परिश्रम करना ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने कहा कि जब तक देश के युवा देश को आगे नहीं बढ़ाते, देश तरक्की के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी देश में उच्च शिक्षा की गरिमामय परंपरा को प्रतिस्थापित करने के लिये कटिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश में 20 विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय खोलने का प्रोजेक्ट हाथ में लिया है और मोदी सरकार प्रत्येक यूनिवर्सिटी को 10 हजार करोड़ रुपये आवंटित करेगी। उन्होंने कहा कि दो साल में ये विश्वविद्यालय कार्य करना शुरू कर देंगे।

श्री शाह ने कहा कि देश में परिवर्तन लाने की मुहिम की जो शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई है, उसे आगे बढ़ाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि पूरा देश इस प्रक्रिया के साथ जुड़ जाए और देश की जनता भी यही चाहती है, इसलिए 2014 के बाद देश में हुए लगभग हर विधानसभा चुनाव में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलाने का जनादेश दिया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुये कहा कि त्रिपुरा में भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि कर्नाटक के युवा भी इस परिवर्तन यात्रा में भागीदार बनें और भ्रष्टाचार-मुक्त कर्नाटक के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि अपने निहित स्वार्थ के लिए, अपने सगे-संबंधियों के लिए सरकार चलानी वाली सरकार कर्नाटक का भला नहीं कर सकती, राज्य के अंतिम व्यक्ति तक के लिए भलाई की सोच रखने वाली सरकार ही कर्नाटक का भला कर सकती है। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति से समाज टूटता है, जुड़ता नहीं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में एक ऐसी सरकार चाहिए जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो, राज्य के अंतिम व्यक्ति तक की भलाई के लिए काम करे और कन्नड़ गौरव को देश में सबसे ऊपर स्थापित कर सके। उन्होंने कहा कि विकास का परिवर्तन करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की होती है लेकिन यदि राज्य सरकार केंद्र की योजनाओं को इम्प्लीमेंट ही न करे तो राज्य आगे नहीं बढ़ सकता।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने युवाओं से अपील करते हुये कहा कि कर्नाटक के युवा आने वाले दिनों में कर्नाटक में एक ऐसी सरकार बनाएं जो कर्नाटक को आगे ले जाने का काम करे। उन्होंने कहा कि विवेकानंद जी के आदर्शों पर चलते हुये "उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक कार्यरत रहो" के संकल्प के साथ हम अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ें। उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुये कहा कि जब तक भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर पुनः प्रतिष्ठित नहीं होती, तब तक हम में से किसी को भी आराम करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि देश का हर गरीब, हर पिछड़ा, दलित, आदिवासी सम्मान के साथ समाज में अपना साथ सुनिश्चित करें, ऐसे भारत के निर्माण के लिए हम सबको मिल कर काम करना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने न्यू इंडिया के निर्माण की परिकल्पना देश के सामने रखी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हम एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं जो गरीबी, गंदगी, भ्रष्टाचार, जातिवाद, सम्प्रदायवाद, आतंकवाद और तुष्टीकरण की राजनीति से मुक्त हो। उन्होंने कहा कि इस नए भारत का निर्माण देश के युवा ही कर सकते हैं क्योंकि जो क्षमताएं भारत के युवाओं में है, वह विश्व में कहीं भी नहीं है। ■

'परिवर्तन के लिए संकल्पबद्ध है कर्नाटक की जनता'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 22 फरवरी को उडुपी (कर्नाटक) में फिशरमेन कन्वेंशन को संबोधित किया और फिशरमेन कम्युनिटी के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा उठाये गये क़दमों पर विस्तार से चर्चा की।

श्री शाह ने कहा कि कर्नाटक की जनता राज्य में परिवर्तन के लिए संकल्पबद्ध है और निश्चित रूप से कर्नाटक में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। उन्होंने कहा कि जिस तरह पिछले चार साल से कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार चल रही है, उसने कर्नाटक को पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार वाली सरकार के नाम से बदनाम कर दिया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार पर एक-के-बाद-एक भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं लेकिन राज्य की कांग्रेस सरकार के माथे पर जूं तक नहीं रेंगती। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया सरकार को भ्रष्टाचार में लज्जा और शर्म भी नहीं आती, वह भ्रष्टाचार को मेडल समझती है। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया सरकार में जो मंत्री भ्रष्टाचार करता है, उसे मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की बजाय कांग्रेस सरकार और बड़ा मंत्री बना देती है।

सिद्धारमैया सरकार पर करारा प्रहार करते हुये राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि राज्य के गरीबों की गाढ़ी कमाई का पैसा कर्नाटक के विकास के लिये खर्च होना चाहिए या सिद्धारमैया सरकार के भ्रष्टाचार के लिए? उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा मछुआरों के विकास के काम आना चाहिए लेकिन सिद्धारमैया सरकार ऐसा नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि चाहे शहर हो या गांव, खेत हो या खलिहान, सागर किनारे का इलाका हो या फिर मैदानी क्षेत्र, सिद्धारमैया सरकार किसी भी जगह विकास करने में विफल रही है।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने फिशरमेन कम्युनिटी के कल्याण के लिए ब्लू रिवोल्यूशन का स्वप्न देखा है, फिशरमेन कम्युनिटी को देश के विकास के साथ जोड़ने का स्वप्न देखा है लेकिन कर्नाटक की कांग्रेस सरकार इसे रोक कर बैठी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने देश के गांव, गरीब, किसान, दलित, मछुआरे, आदिवासी, महिलायें एवं युवाओं के कल्याण के लिए लगभग 112 योजनाओं की शुरुआत की है लेकिन कांग्रेस की कर्नाटक सरकार इसे नीचे तक पहुंचने नहीं देती। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गरीबों के कल्याण के लिए चार साल में जितने काम किये, उतना काम कांग्रेस आजादी के 70 सालों में भी नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 'आयुष्मान भारत' की योजना लेकर आये हैं जिसके तहत भारत के लगभग 10 करोड़ गरीब परिवारों को पांच लाख रुपये सालाना तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा, इस योजना को देश की जनता ने अभूतपूर्व प्यार देते हुये 'नमो केयर' की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत देश के हर गरीब परिवार को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है जिसमें से लगभग साढ़े तीन करोड़ गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन देने का काम पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 2022 तक देश के घर गरीब को घर देने का लक्ष्य निर्धारित किया है, कर्नाटक में भी हर गरीब, हर फिशरमेन फैमिली को अपना घर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार और कर्नाटक में श्री येदुरप्पा जी के नेतृत्व में बननेवाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिल कर इस कार्य को पूरा करेगी।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जब श्री नरेन्द्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सागरखेरू योजना शुरू की थी जिसके तहत केवल गुजरात में सागरखेरू के विकास के लिए अब तक लगभग 16 हजार रुपये खर्च किये गये, इस क्षेत्र के हर घर में बिजली पहुंचाई गई, स्कूल खोले गये, समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था की गई और लोगों के जीवन-स्तर को ऊपर उठाया गया। उन्होंने कहा की कर्नाटक में

लगभग 300 किलोमीटर का सागर किनारा पड़ता है और मोदी जी ने इस क्षेत्र के विकास के लिये कई कार्यक्रमों की शुरुआत की है। उन्होंने कहा किकांग्रेस की यूपीए सरकार ने 2009-2014 के बजट में फिशरमेन कम्युनिटी के विकास व कल्याण के लिए जहां केवल 1700 करोड़ रुपये दिए थे, वहीं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इसे बढ़ा कर 2900 करोड़ रुपये कर दिया है उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने फिशरमेन को भी किसान का स्टेटस दिया है ताकि फिशरमेन भी किसान क्रेडिट कार्ड का फायदा उठा सकें। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने FIDF संस्था के माध्यम से फिशरमेन के कल्याण के लिए अलग से 7500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि पहले फिशरमेन को 29 रुपये के प्रीमियम पर एक लाख रुपये का बीमा मिलता था जबकि मोदी सरकार ने केवल 20 रुपये के प्रीमियम पर दो लाख रुपये के बीमा का प्रावधान किया है। ■

भाजपा की शानदार जीत

भाजपा ने 75 में से 47 सीटें जीती

@vijayrupanibjp
गुजरात नगरपालिका चुनावों के नतीजे राज्य में विकास पर लोगों का जनमत संग्रह है।

गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर परचम लहराया। राज्य में भाजपा ने नगर निकाय चुनावों में 75 में से 47 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस के खाते में 16 सीटें गईं। गौरतलब है कि 75 नगर निगम/नगर पालिकाओं, दो जिला पंचायत और 17 तालुका पंचायतों के लिए 17 फरवरी को चुनाव हुए थे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त वारेश सिन्हा के अनुसार, ''भाजपा ने 47, कांग्रेस ने 16, और राकांपा और बसपा ने एक-एक नगरपालिका में जीत हासिल की। निर्दलीय उम्मीदवारों की झोली में चार नगरपालिकाएं गई, जबकि छह नगरपालिकाएं त्रिशंकु रहीं, जहां किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला।'' विदित हो कि पिछले बरस दिसंबर में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने लगातार छठी बार जीत दर्ज करते हुए 99 सीटें जीतीं थीं, जबकि कांग्रेस को 182 सदस्यीय विधानसभा में 77 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था।

श्री सिन्हा ने बताया कि 24 जिलों की 75 नगरपालिकाओं की 2,060 सीटों में से भाजपा ने 1,167 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस के पाले में 630 सीटें गई। राकांपा ने 28 और बसपा ने 15 सीटें जीतीं। अन्य छोटी राजनीतिक पार्टियों ने 18 सीटें अपने नाम की हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशियों ने 202 सीटें हासिल कीं। उन्होंने कहा मतगणना की प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर मेहसाणा जिले के वडनगर में भाजपा ने 28 सीटों में से 27 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि एक सीट कांग्रेस के खाते में गई।

चुनाव परिणाम की घोषणा के साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी मुख्यालय में जश्न मनाया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने इस जीत को राज्य सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन और आम जनता समर्थक नीतियों में लोगों के 'अटूट' विश्वास का सबूत करार दिया। उन्होंने कहा, 'गुजरात की जनता का भाजपा में निरंतर अपना विश्वास प्रकट करना भाजपा की प्रदेश सरकार और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सुशासन व लोक कल्याणकारी नीतियों में जनता के अटूट विश्वास को प्रमाणित करता है।' प्रदेश भाजपा प्रवक्ता श्री भरत पांड्या ने कहा कि यह जीत कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति और कार्यक्रमों के खिलाफ है। गुजरात के लोगों ने एक बार फिर से कांग्रेस की नकारात्मकता को खारिज कर दिया है। ■

भाजपा ने दिए 'भ्रष्टाचार-मुक्त' सरकार, पहले था 'भ्रष्टाचार-युक्त' सरकारः अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस के शासनकाल में केन्द्रीय धनराशि ''भ्रष्टाचार के दलदल'' में जाती थी लेकिन अब केन्द्रीय धनराशि राज्यों के खजाने में जाती है। लम्बे समय बाद राज्य को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में एक ईमानदार और पारदर्शी सरकार मिली है।

श्री शाह ने 15 फरवरी को जींद में आयोजित ''युवा हुंकार'' रैली को संबोधित करते हुए कहा, ''कांग्रेस के लोग हमसे पूछते हैं कि राज्य को इतनी धनराशि देने के लिए कहां से आती है। हम उन्हें बताते है कि वे भी देते थे लेकिन अंतर यह है कि वे इसे अपने साथियों में वितरित करते थे और हम हरियाणा राज्य को देते है।''

श्री शाह ने केंद्र एवं हरियाणा की सरकार को किसान हितैषी सरकार बताया। उन्होंने कहा कि आज विरोधी भी प्रदेश की भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगा सकते हैं। वह समय बीत गया जब हरियाणा में 'तबादला उद्योग' चलता था।

श्री शाह ने हरियाणा की पूर्व कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि संप्रग सरकार में 13वें वित्त आयोग में हरियाणा को केवल 14,900 करोड़ रूपये जारी किये गये थे। वहीं, भाजपा ने 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के बाद हरियाणा को 42 हजार करोड़ रुपए जारी किये।

श्री शाह ने कहा,'' वर्ष 2014 में आपने मोदी जी को जनादेश दिया और इसके बाद खट्टर जी को जनादेश दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दोनों सरकारों ने आप लोगों को भ्रष्टाचार-मुक्त शासन दिया है।'' भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि केन्द्र और हरियाणा में कांग्रेसनीत सरकारों के दौरान 12 लाख करोड़ रुपये के घोटाले और भ्रष्टाचार हुए लेकिन हमें अब सत्ता में आये चार वर्ष हो गये है और हमारे विरोधी हम पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा पाये। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों के लिए 'वन रैंक वन पेंशन' दशकों से लटकी पड़ी थी लेकिन मोदी सरकार ने सत्ता में आने के एक वर्ष के भीतर ही इस संबंध में निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार लोगों के हित में आयुष्मान भारत योजना, नमो केयर (मोदी केयर) जैसी कई योजनाएं लाई।

राज्य की खट्टर सरकार की प्रशंसा करते हुए श्री शाह ने कहा कि राज्य केरोसिन मुक्त बन गया है। राज्य सरकार ने लोगों के हित में कई योजनाएं शुरू की हैं जो प्रशंसनीय हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि भाजपा वर्ष 2019 में हरियाणा से सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करें। इस बीच राज्य में 16 पार्टी कार्यालयों की आधारशिला रखे जाने के समारोह

आयोजित हुए और श्री शाह ने यहां एक कार्यालय का उद्घाटन किया।

श्री शाह ने कहा कि हरियाणा में पहले की सरकारें जाति के आधार पर भेदभाव करती थीं लेकिन मनोहर लाल खट्टर सरकार की कोई जाति नहीं है और वह सबका साथ और सबका विकास के नारे पर काम कर रही है। श्री शाह ने कहा, ''राज्य में बेटी बचाओ अभियान सफल रहा है। बेटियों का औसत राज्य में 950 को पार कर गया है। हरियाणा खिलाड़ियों, वीरों और युवाओं की भूमि है। केंद्र सरकार ने सैनिकों के लिए वन रैंक पेंशन देकर उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया है।''

उन्होंने कहा, "यह चुनावी सभा नहीं है। यह कार्यकर्ताओं की बैठक है। मैं आपके माध्यम से हरियाणा की जनता से अपील करूंगा कि वर्ष 2019 में हरियाणा की सभी सीटों पर जीत दिलाएं।"

रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री मनोहरलाल खट्टर ने कहा कि उनकी सरकार के पिछले तीन वर्ष के शासन में राज्य को भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और क्षेत्रवाद से छुटकारा मिला है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पिछली सरकार के भ्रष्टाचार और लूट की राजनीति को खत्म किया। उन्होंने कहा कि लगभग साढे तीन वर्ष पूर्व देश के सामने बहुत चुनौतियां थी लेकिन आज मोदी सरकार में देश विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।

श्री खट्टर ने कहा कि वर्तमान सरकार ने लूटतंत्र को समाप्त करने का काम किया है। आज हरियाणा निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है। उन्होंने दावा किया कि यह समय विकास कार्यों को गिनवाने का नहीं बल्कि विकास के बूते पर आगे बढ़ने का है। विपक्षी पार्टियों की निंदा करते हुए खट्टर ने कहा कि लोग भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और क्षेत्रवाद की राजनीति से ऊब चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की मौजूदा सरकार किसानों, महिलाओं और युवाओं समेत सभी वर्गों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए काम कर रही है। ■

भाजपा प्रशिक्षण महाभियान अगले चरण की ओर

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व बुनकर के प्रशिक्षण हेतु चिंतन बैठक संपन्न

भाजपा केंद्रीय कार्यालय में 9 फरवरी को अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा एवं बुनकरों के प्रशिक्षण हेतु चिंतन बैठक संपन्न हुई। इन बैठकों की अध्यक्षता भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव श्री मुरलीधर राव ने की। इस बैठक में श्री वी. सतीश (राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री), श्री महेश चंद्र शर्मा (राष्ट्रीय संयोजक, प्रशिक्षण), श्री सुनील पांडे (राष्ट्रीय सह संयोजक, प्रशिक्षण), श्री रविन्द्र साठे (सदस्य-प्रशिक्षण समिति), श्री शिवशक्ति बक्सी (सदस्य-प्रशिक्षण समिति) एवं श्री हेमंत गोस्वामी (सदस्य-प्रशिक्षण समिति) उपस्थित थे।

बैठकों को संबोधित करते हुए श्री मुरलीधर राव ने कहा कि हमारी पार्टी संगठन आधारित पार्टी है और संगठन का आधार कार्यकर्ता होता है। जनता के बीच जाकर पार्टी का विचार पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य हमारे कार्यकर्ता ही करते हैं। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान की सफल शुरुआत 2015 में की गयी। यह भागीरथ कार्य था, हमें मंडल स्तर तक जाकर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना था। ढाई साल के अथक प्रयासों से हमने 10 लाख से ऊपर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया है। यह अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। पार्टी ने 11 करोड़ सदस्य बनाकर विश्व कीर्तिमान प्रस्थापित किया और यह सोचा गया कि 11 लाख सक्रिय कार्यकर्ताओं को हम प्रशिक्षित करें, इसमें हम काफी हद तक कामयाब हुए हैं। इस प्रक्रिया में कुछ मूल विषय हैं जैसे भाजपा का इतिहास एवं विकास, एकात्म मानववाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, राष्ट्र के समक्ष चुनौतियां, विचार परिवार एवं सैद्धांतिक अधिष्ठान, कार्यकर्ता विकास इत्यादि। मंडल स्तर तक प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद प्रशिक्षण महाभियान का द्वितीय चरण भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया गया। द्वितीय चरण में संस्थागत एवं अन्य वर्गों का प्रशिक्षण प्रारूप तैयार होना है। संस्थागत प्रशिक्षण में सभी प्रमुख मोर्चे, विभाग, प्रकल्प आदि का प्रशिक्षण होगा। अन्य प्रशिक्षण वर्गों में सांसद, विधायक, सहयोगी, शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय निकाय, मीडिया, सहकारिता इत्यादि से संबंधित कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण होना है।

हम आज 80% भू-भाग पर सत्ता में हैं और 125 करोड़ लोगों को दिशा निर्देशित कर रहे हैं। सत्ता हमारे लिए समाज परिवर्तन का साधन है और कार्यकर्ता इस परिवर्तन का मुख्य अंग है। इसलिए यह जरूरी है के कार्यकर्ताओं में संस्कार एवं Nation First की भावना को प्रशिक्षण के जरिए जगाया जाए। यही कारण हमें Party with a Difference का ओहदा बनाने रखनें में सफल बनाएंगे।

अनुसूचित जाति मोर्चा कार्यकर्ता प्रशिक्षण के संबंध में श्री मुरलीधर राव ने कहा 'हमारा देश संविधान-संचालित देश है। यह अध्यात्मिक भूमि है। यह देश वेद-उपनिषद-कबीर-रविदास-अंबेडकर का देश है। सामाजिक अंतर्विरोध खत्म कर हमें देश को एक बनाना है। सत्ता परिवर्तन का साधन-मात्र है और हमारे कार्यकर्ता इस समाज परिवर्तन का मुख्य घटक है, इसलिए हमें कार्यकर्ता को प्रशिक्षण के माध्यम से तैयार करना है।'

मोर्चा अध्यक्ष श्री विनोद सोनकर ने कहा कि इस बैठक में जो भी निर्णय लिए जाएंगे उनको मंडल स्तर तक लागू किया जाएगा। श्री वी. सतीश ने बताया कि कार्यकर्ता को वैचारिक चुनौतियों के लिए तैयार करना चाहिए।

अनुसूचित जनजाति मोर्चा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मुरलीधर ने कहा 'जहां भी अनुसूचित जातियों की संख्या ज्यादा हैं वहां वहां भाजपा को सफलता मिली है कि समाज को योगदान, आध्यात्मिक, वीरता, सम्राज्य, सांस्कृतिक एकता आदि में अमूल्य है। मोर्चा अध्यक्ष श्री नेताम ने कहा कि 2019 के चुनावों से पहले हमें प्रशिक्षण गतिविधियों को पूर्ण करना है।

बुनकर कार्यकर्ता प्रशिक्षण को लेकर महेश चंद्र शर्मा ने कहा कि बुनकर समाज के कार्यकर्ता राष्ट्रवादी हैं, यह देश का अभिन्न हिस्सा है। हमें इस समाज में से नेतृत्व निर्माण करना है यह भी हमें प्रशिक्षण में बताना होगा कि कौन कौन से महापुरुष इस समाज में हुए हैं। कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना होगा कि बुनकर समाज में जाकर कैसे काम करें, कैसी बात करें इत्यादि। इन सभी बैठकों में प्रशिक्षण के स्तर, अवधि, विषय एवं रिसोर्स पर्सन्स तय किये गए। ■

व्यावसायिक कोयले के खनन में निजी क्षेत्र का प्रवेश

1973 में कोयला खनन के राष्ट्रीयकरण के बाद सबसे महत्वाकांक्षी सुधार

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने 20 फरवरी को कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 और खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम 1957 के तहत कोयले की बिक्री के लिए खानों/ब्लॉकों की निलामी पद्धति को मंजूरी दे दी। व्यावसायिक कोयले के खनन को निजी क्षेत्र के लिए खोला जाना 1973 में इस क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण के बाद कोयला क्षेत्र का सबसे महत्वाकांक्षी सुधार है।

उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 24.09.2014 के अपने आदेश के जरिए कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनिमय 1973 के तहत 1993 से विभिन्न सरकारी और निजी कंपनियों को दिए गए कोयला खानों और ब्लॉकों का आवंटन रद्द कर दिया था। पारदर्शिता लाने तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संसद द्वारा 30.03.2005 को कोयला खान विशेष उपबंध विधेयक 2015 को अधिसूचित किया गया था। इस अधिनियम में कोयले की बिक्री तथा नीलामी प्रक्रिया के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं।

यह प्रक्रिया पारदर्शिता लाने तथा कारोबारी सुगमता को उच्च प्राथमिकता देती है और साथ ही यह सुनिश्चत करती है कि प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल राष्ट्रीय विकास के लिए हो। नीलामी प्रक्रिया नीचे से ऊपर के क्रम में होगी, जिसमें बोली के मानक रुपये और टन के मूल्य प्रस्ताव के रूप में होंगे, जिसका भुगतान कोयले के वास्तविक उत्पादन के आधार पर राज्य सरकार को किया जाएगा। कोयला खानों से निकाले गए कोयले की बिक्री और उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस सुधार से एकाधिकार से प्रतिस्पर्धा के युग की बढ़ते हुए कोयला क्षेत्र में दक्षता आने की उम्मीद है। यह कोयला क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगा और हरसंभव बेहतरीन प्रौद्योगिकी का रास्ता खोलेगी।

ज्यादा निवेश होने से कोयले क्षेत्रों विशेषकर खनन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे, जिससे इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास पर असर पड़ेगा। इससे ऊर्जा भी सुनिश्चित होगी, क्योंकि भारत में 70 प्रतिशत बिजली का उत्पादन ताप विद्युत संयंत्रों में होता है। यह सुधार कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ ही कोयले के आवंटन को जवाबदेह बनाएगा तथा किफायती कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा जिससे उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मिल सकेगी।

कोयले की बिक्री के लिए कोयला खानों की नीलामी से अर्जित होने वाला पूरा राजस्व कोयला वाले राज्यों को मिलेगा। अतः इस प्रक्रिया से उन्हें अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी, जिसका इस्तेमाल वे अपने पिछड़े क्षेत्रों और वहां के लोगों तथा जनजातियों के विकास के लिए कर सकेंगे। देश के पूर्वी हिस्से के राज्य इससे विशेष रूप से लाभान्वित होंगे। ■

जनवरी में खुदरा महंगाई दर 5.07 फीसदी

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने 12 फरवरी को जनवरी, 2018 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित महंगाई दर के आंकड़े जारी किए। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सीपीआई आधारित महंगाई दर 5.21 फीसदी (अनंतिम) रही। इसी तरह शहरी क्षेत्रों के लिए सीपीआई आधारित महंगाई दर जनवरी, 2018 में 4.93 फीसदी (अनंतिम) आंकी गयी। ये दरें दिसंबर, 2017 में क्रमशः 5.27 तथा 5.09 फीसदी (अंतिम) थीं।

केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जनवरी, 2018 के लिए उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) पर आधारित महंगाई दर के आंकड़े भी जारी किए। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सीएफपीआई आधारित महंगाई दर 5.05 फीसदी (अनंतिम) रही। इसी तरह शहरी क्षेत्रों के लिए सीएफपीआई आधारित महंगाई दर जनवरी, 2018 में 4.06 फीसदी (अनंतिम) आंकी गई। ये दरें दिसंबर, 2017 में क्रमशः 5.08 तथा 4.71 फीसदी (अंतिम) थीं।

अगर शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों पर समग्र रूप से गौर करें, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित महंगाई दर जनवरी, 2018 में 5.07 फीसदी (अनंतिम) आंकी गई है, जो जनवरी, 2017 में 3.17 फीसदी (अंतिम) थी। वहीं, सीपीआई पर आधारित महंगाई दर दिसंबर, 2017 में 5.21 फीसदी (अंतिम) थी। इसी तरह यदि शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों पर समग्र रूप से गौर करें, तो उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) पर आधारित महंगाई दर जनवरी, 2018 में 4.70 फीसदी (अनंतिम) रही है, जो जनवरी, 2017 में 0.61 फीसदी (अंतिम) थी। वहीं, सीएफपीआई पर आधारित महंगाई दर दिसंबर, 2017 में 4.96 फीसदी (अंतिम) थी।

गौरतलब है कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के लिए आधार वर्ष को 2010=100 से संशोधित करके 2012=100 कर दिया है। ■

दिसंबर, 2017 में औद्योगिक विकास दर 7.1 फीसदी

दिसंबर, 2017 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) 130.3 अंक रहा, जो दिसंबर, 2016 के मुकाबले 7.1 फीसदी ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि दिसंबर, 2017 में औद्योगिक विकास दर 7.1 फीसदी रही। इसी तरह अप्रैल- दिसंबर, 2017 में औद्योगिक विकास दर पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 3.7 फीसदी आंकी गई।

गौरतलब है कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 12 फरवरी को दिसंबर, 2017 के लिए जारी किये गये औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के त्वरित आकलन (आधार वर्ष 2011-12=100) से उपर्युक्त जानकारी मिली। 14 स्रोत एजेंसियों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर आईआईपी का आकलन किया जाता है। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और उर्वरक विभाग भी इन एजेंसियों में शामिल हैं। दिसंबर, 2017 में खनन, विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) एवं बिजली क्षेत्रों की उत्पादन वृद्धि दर दिसंबर, 2016 के मुकाबले क्रमशः 1.2 फीसदी, 8.4 फीसदी तथा 4.4 फीसदी रही। इसी तरह अप्रैल- दिसंबर 2017 में इन तीनों क्षेत्रों यानी सेक्टरों की उत्पादन वृद्धि दर पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में क्रमशः 2.8, 3.8 तथा 5.1 फीसदी आंकी गई है।

उपयोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार दिसंबर, 2017 में प्राथमिक वस्तुओं (प्राइमरी गुड्स), पूंजीगत सामान, मध्यवर्ती वस्तुओं एवं बुनियादी ढांचागत/निर्माण वस्तुओं की उत्पादन वृद्धि दर दिसंबर, 2016 की तुलना में क्रमशः 3.7 फीसदी, 16.4 फीसदी, 6.2 फीसदी और 6.7 फीसदी रही। जहां तक टिकाऊ उपभोक्ता सामान का सवाल है, इनकी उत्पादन वृद्धि दर दिसंबर, 2017 में 0.9 फीसदी रही है। वहीं, गैर-टिकाऊ उपभोक्ता सामान की उत्पादन वृद्धि दर दिसंबर, 2017 में 16.5 फीसदी रही।

इस दौरान उच्च धनात्मक उत्पादन वृद्धि दर दर्ज करने वाली कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं में ट्रकों की बॉडी, लॉरी एवं ट्रेलर (254.1%), एपीआई और एंटी-हाइपर-ट्राइग्लिसराइडेमिक्स (जैसे सिमवास्टाटिन, एटोरवास्टाटिन, आदि) सहित हाइपो-लिपिडेमिक एजेंट, उच्च रक्तचाप-रोधी (250.4 प्रतिशत) जहाज निर्माण और उसके कलपुर्जे' (144.1%), पाचन एंजाइम और एंटासिड (पीपीआई ड्रग्स) सहित (88.4%), 'मीटर (बिजली और गैर-बिजली)' (77.1%), 'डिकंटर अपकेंद्रित्र सहित विभाजक' (67.8%), 'धुरा' (48.7%), वाणिज्यिक वाहन (40.6 प्रतिशत), दोपहिया वाहन (मोटरसाइकिल/स्कूटर) (36.0 प्रतिशत) और सीमेंट-सभी प्रकार (20.4 प्रतिशत) शामिल हैं। ■

रक्षा खरीद परिषद् ने 1850 करोड़ रुपये के बराबर की खरीद को मंजूरी दी

रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद् (डीएसी) ने 20 फरवरी को बैठक आयोजित की एवं 1850 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की पूंजीगत खरीद प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की।

इनमें ऑर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड (ओएफबी) से 1125 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत पर मैकेनाइज्ड थल सेना एवं अन्य शस्त्रों तथा सेवाओं के लिए इंफैंटरी कॉम्बैट वेहिकल (बीएमपी-2/2के) की अनिवार्य गुणवत्ता की खरीद शामिल है। यह खरीद मैकेनाइज्ड बलों की त्वरित तैनाती में टुकड़ियों की संचालनगत आवश्यकता की पूर्ति करेगी।

भारतीय नौसेना ने हिन्द महासागर क्षेत्र में जल माप चित्रण संबंधी संचालनों में अग्रणी भूमिका निभाई है। डीएसी ने बंदरगाहों, हार्बरों, विशिष्ट आर्थिक जोन, आदि में नौसेना की बढ़ती जल माप चित्रण संबंधी सर्वे आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सर्वेक्षण प्रशिक्षण पोत (एसटीवी) की खरीद को मंजूरी दी। पोत का निर्माण 626 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से इंडियन शिपयार्ड्स द्वारा बाई (इंडियन-

आईडीडीएम) के तहत आरंभ किया जाएगा। ■

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बजट आवंटन में 12.10 प्रतिशत की वृद्धि

वर्ष 2018-19 के लिए केंद्रीय बजट में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बजट प्रावधान में 12.10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। मंत्रालय को वर्ष 2017-18 में 6908.00 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था, जबकि वर्ष 2018-19 के लिए यह राशि बढ़कर 7750.00 करोड़ रुपये कर दी गई है। इसके साथ ही वर्ष 2017-18 के अनुपात में वर्ष 2018-19 में योजनाओं के लिए बजट आवंटन में 11.57 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। वर्ष 2017-18 के मुकाबले वर्ष 2018-19 में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए बजट आवंटन में 41.03 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

अनुसूचित जातियों के लिए वेंचर कैपिटल निधि के समान अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी एक नई योजना वेंचर कैपिटल निधि की शुरूआत की जाएगी। इसके लिए प्रारम्भिक तौर पर 200 करोड़ रुपये की निधि बनाई गई है। वर्ष 2018-19 में इसके लिए 140 करोड़ रुपये प्रदान किये जाएंगे। हाथ से मैला ढोने वाले 13,587 व्यक्तियों और उन पर निर्भर व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। हाथ से मैला ढोने वाले 809 व्यक्तियों और उन पर निर्भर व्यक्तियों को आश्रितों को बैंक द्वारा ऋण प्रदान किये जाएंगे।

पहली बार नशे से पीड़ित व्यक्तियों की पहचान के लिए राष्ट्रीय सर्वेक्षण किया जा रहा है। यह सर्वेक्षण 185 जिले, 1.5 लाख घरों और 6 लाख व्यक्तियों पर किया जाएगा। इस सर्वेक्षण की शुरुआत हो चुकी है और इसके मार्च-अप्रैल, 2018 तक पूरा होने की संभावना है। पहली बार नशे से पीड़ित व्यक्तियों के पुर्नवास के लिए 200 करोड़ रुपये प्रदान किये जाएंगे। देशभर में 15 जिलों में विशेष गहन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नशे से पीड़ित व्यक्तियों के पुर्नवास की योजना के अर्न्तगत विभाग द्वारा सभी केन्द्रों में स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाएगी। नशा छुड़ाने वाले केंद्रों का नाम बदलकर उपचार चिकित्सालय किया जाएगा। इस प्रकार के उपचार चिकित्सालय राज्यों की प्रमुख जेलों, बाल सुधार गृहों और प्रमुख सरकारी अस्पतालों में स्थापित किये जाएंगे।

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृति में आय की सीमा 44,500 रुपये बढ़ाकर 2.5 लाख प्रतिवर्ष की गयी है। अनुसूचित जाति के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृति में आय की सीमा 2 लाख रुपये बढ़ाकर 2.5 लाख प्रतिवर्ष की गयी है। आवासी विद्यार्थी के लिए वृत्तिका 150 रुपये से बढ़ाकर 225 रुपये और छात्रावास में रहने वाले के लिए 350 रुपये से बढ़ाकर 525 रुपये की गयी है। अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए निशुल्क कोचिंग के लिए आय की सीमा 4.5 लाख से बढाकर 6 लाख रुपये की गयी है। स्थानीय छात्रों के लिए वृत्तिका 1500 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये और दूसरे शहरों से आये विद्यार्थियों के लिए 3000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये की गयी है।

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृति में भी वृद्धि की गयी है। पूर्व में कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8 और कक्षा 9 से 10 के लिए आवासी विद्यार्थियों को 10 माह तक क्रमशः 25, 40 और 50 रुपये प्रदान किये जाते थे। अब कक्षा 1 से 10 के लिए इसे बढ़ाकर 100 रुपये प्रतिमाह किया गया है। पूर्व में कक्षा 3 से 8 और 9 से 10 के छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों दी जाने वाली छात्रवृत्ति को क्रमशः 200 और 250 को बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह किया गया है। इस योजना के अर्न्तगत सभी विद्यार्थियों को वर्ष में एक बार 500 रुपये तदर्थ राशि के रूप में प्रदान किए जाते हैं। अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृति के अर्न्तगत प्रत्येक छात्र को दी जाने सहायता राशि 25,000 रुपये से बढ़ाकर 28,000 रुपये की गई है। ■

हमारे कार्य का आधार धर्म होना चाहिए

| दीनदयाल उपाध्याय |

हम जिस वैभव की प्राप्ति करना चाहते हैं, वह धर्मयुक्त होना चाहिए। जिससे धारणा होती है, वह धर्म होना चाहिए। व्यक्ति और समाज जिन सिद्धांतों के आधार पर उन्नति करें, वह धर्म होना चाहिए। व्यक्ति की सब क्रियाएं क्यों हैं? क्यों रोटी खाते हैं? हम सब पेट के लिए रोटी खाते हैं। कहीं रोटी खाते हैं, कहीं अच्छी पूरियां खाते हैं। एक ठाकुर नाई को साथ लेकर ससुराल गए। रास्ते में स्वयं ने तो कचौरी खाई और नाई को पैसे दिए कि जाकर चने खा ले। ससुराल में पहुंचकर नाई ने वहां के लोगों से कह दिया कि ठाकुर साहब का पेट ख़राब है। वे केवल मूंग की दाल ही खाएंगे। अब दो-तीन दिन तक मूंग की दाल ही उन्हें खिलाई गई। इस तरह नाई ने अपना बदला ले लिया। व्यक्ति सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है। लेकिन आज का सुख कल का दुःख भी तो हो सकता है। आज कुल्फी खाई, कल गला भी ख़राब हो सकता है। लोग कल के सुख के लिए आज दुःख भी उठाते हैं। मसूरी का सुख ध्यान में रखकर लोग वहां की घुमावदार सड़कों पर चलते हुए उल्टियां करते हैं। लेकिन मसूरी की कल्पना उनके मन में होती है। इसलिए वह दुःख बरदाश्त हो जाता है। स्थायित्व का बहुत महत्त्व होता है। दाल-रोटी को हम अपना मानते हैं। लेकिन जहां पकवान मिलें और साथ में तिरस्कार भी हो तो वह पकवान किस काम का? भगवान् कृष्ण ने दुर्योधन की मेवा छोड़कर विदुर के घर साग क्यों खाया? सुख केवल शरीर का ही नहीं होता, सुख तो मन का होता है। मन में दुःख हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता।

एक बार लोग भोजन कर रहे थे। तभी तार आया कि रेलगाड़ी की टक्कर में किसी की मृत्यु हो गई है। वे अभी-अभी सुख का अनुभव कर रहे थे, एकदम से दुःख का समाचार मिला तो अच्छा न लगा। लोग होटल का खाना छोड़कर माता के हाथ का बना भोजन क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि उसमें मन का सुख मिलता है। भीम कितना खाना खाते थे, लेकिन जब तक मां कुंती के हाथ से एक-दो निवाले न खा लें, उन्हें सुख नहीं मिलता था, उनकी भूख ही नहीं मिटती थी। हमारे प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाए तो बुद्धि का भी सुख प्राप्त हो जाता है। शरीर और मन से परे आत्मा का सुख होता है। सुंदर फूल देखकर आनंद और मुरदे को देखकर दुःख क्यों प्राप्त होता है? एक बार कहीं आग लग गई। बच्चा अंदर ही रह गया। उसकी मां छटपटा रही थी। एक नौजवान बच्चे को निकाल लाया। शरीर को कुछ नुक़सान हुआ, लेकिन फिर भी उसे सुख प्राप्त हुआ। बच्चे को बचाने की भावना से उसे आत्मिक सुख प्राप्त हुआ।

सुख चार प्रकार के होते हैं- भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक। जो रास्ता हमें इन चारों सुखों से मिला दे, वही धर्म का रास्ता है। अंदर और बाहर के जो सुख हैं। यानी भौतिक और आध्यात्मिक जो सुख हैं, ये धर्म के हैं। इसलिए दोनों में से एक की भी अवहेलना हमें नहीं करनी है। जो एक की उपासना करता है, वह ग़लत है। रोटी, कपड़ा और मकान ही नहीं चाहिए। हमें आत्मिक सुख भी चाहिए। अपनी दृष्टि बिगाड़कर हमें रोटी नहीं चाहिए। सम्मानपूर्वक मिलनी चाहिए। रहीम ने एक जगह कहा है, पेट तू पीठ होना चाहिए था। क्योंकि यदि भर जाता है तो दृष्टि बिगाड़ता है, यानी ग़लत कार्यों को उकसाता है और यदि ख़ाली रहता है तो ठीक रहता है। अभ्युदय और निश्रेयस्य दोनों की प्राप्ति जिससे हो, वह धर्म केवल एक नहीं है। उस धर्म को प्राप्त करने का विचार, उस सुख को प्राप्त करने का विचार केवल व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। काम करके, परिश्रम करके, पुरुषार्थ करके, कर्मयोग द्वारा ही यह सुख प्राप्त हो सकता है।

कर्म का सिद्धांत हमारे यहां विशेष है। एक और विशेष चीज़ है 'कमाने वाला खाएगा।' इस विचार को मान्यता नहीं दी गई है। यह बात तो अच्छी है, लेकिन सभी जानते हैं कि कल न कमाने का काल भी तो आ सकता है। बचपन था तब भी कमाते नहीं थे, किंतु आज कमाएंगे हम और खाएगा कोई और, यह प्रकृति नहीं है। प्रकृति के ऊपर भी एक चीज है संस्कृति। कमाने वाले खिलाएंगे—यही हमारे

यहां का सिद्धांत है। प्रकृति में यही है कि जो जैसा कर्म करेगा, वैसा फल पाएगा, हम दूसरों के लिए कर्म करेंगे-यही हमारा यज्ञ है। यह यज्ञ धर्म संस्कृति का आधार है। वृक्ष अपने फल कभी नहीं खाता। वह अपने संपूर्ण जीवन रस को फल में रख देता है। वह तो पत्थर मारने वाले को भी फल देता है। नदियां अपना सारा पानी खुद ही पीने लग जाएं, वृक्ष अपने फल ख़ुद ही खाने लग जाएं तो दूसरों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। सृष्टि का चक्र ही रुक जाएगा। सबका आधार कर्म है।

कर्म यज्ञमय है। यज्ञ कर्म हमारी ब्रह्ममयी भावना से है, जिसमें से एकात्मता पैदा होती है। पेड़, गाय, चंडाल, ब्राह्मण—सभी में इसका दिग्दर्शन करता है। मां-बेटे में अपना स्वरूप देखकर, उसे अपना समझकर सुख मानती है। हमारे यहां समानता का नहीं, आत्मीयता का सिद्धांत है। संपूर्ण विश्व के अंदर एकात्मकता का भाव रहता है। फिर प्रत्येक काम में सुसूत्रता आती है। कुटुंब का आधार समानता नहीं, एकात्मता है। विद्या, आयु, भौतिक सामर्थ्य, खाने-पीने किसी में समान नहीं। कुटुंब में समानता केवल छोटी सी बात की है। वह है एक ही कुटुंब की। गोत्र आदि की। पश्चिम ने समानता का नारा दिया। वह बस जेल में है, प्रत्येक करेगा अपनी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक पाएगा अपनी आवश्यकता के अनुसार निर्णय कौन करेगा कि किस की कितनी क्षमता है तथा कितनी आवश्यकता है, जहां पर हरेक ने सोचा कि मैं ही क्यों काम करूं? एक कुटुंब में एक भाई अच्छा एथलीट था, काम नहीं करता था। घर में चाय नहीं बनी थी। भाभी ने कहा, 'कमाओ'। भाई भी घर में आकर बैठ गया। उसने शतरंज खेलना प्रारंभ कर दिया। तीसरे ने कविता लिखनी शुरू की, धीरे-धीरे घर ख़त्म होने लगा। घर तब ही चल सकता है, जब ज्यादा से ज्यादा कमाया जाए और कम से कम उसमें से लिया जाए।

घर में आत्मीयता होगी, तभी ऐसा हो सकता है। मां तभी सवेरे से काम शुरू करती है। रात्रि तक काम में लगी रहती है। क्या खाती है? बच्चे को खिलौना चाहिए। सबके अंदर का साम्य भाव चाहिए, फिर अंदर से यज्ञ भाव उत्पन्न होता है। राजा को प्रजा के लिए और प्रजा को राजा के लिए सोचना चाहिए। पति-पत्नी के लिए और पत्नी-पति के लिए सोचे। इसी भावना से समाज की रचना हो सकती है और सृष्टि भी इसी आधार पर खड़ी है। हमारे यहां पुनर्जन्म में विश्वास किया जाता है। लोग कहते हैं। कि अगले जन्म में यह कर्म साथ-साथ जाएगा। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, लेकिन यह भी सत्य है कि तुम अकेले नहीं हो, सृष्टि के साथ बंधे हो। अकेले को आनंद नहीं आ सकता। रोटी हमारे अकेले के लिए नहीं है। उसके लिए बहुत लोगों को काम करना पड़ता है। इसी तरह कपड़ा बनाया जाता है। हमारा सारा जीवन दूसरे पर अवलंबित है। केवल हमारे समाज पर ही नहीं पूरी सृष्टि पर हमारा जीवन अवलंबित है। तूफ़ान, आंधी, वर्षा के लिए भी हम दूसरों पर निर्भर हैं।

सारे सुखों के साथ-साथ मानसिक सुख भी हमारे लिए जरूरी है। एक बार एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को एक अंगूठी लाकर दी। सुबह उसकी अंगूठी की तरफ़ किसी का भी ध्यान नहीं गया। वह बहुत परेशान थी कि कोई उसकी अंगूठी देखे और तारीफ़ करे, लेकिन किसी ने भी उसकी तरफ़ ध्यान नहीं दिया। उस स्त्री ने अपने घर में आग लगा दी। जब सब लोग आग बुझाने आए तो वह अंगूठी वाले हाथ से इशारा कर करके बताती रही कि पानी इधर डालो, उधर डालो। अचानक किसी का ध्यान उसकी अंगूठी पर गया। उसने तारीफ़ की और पूछा कि कहां से लाई। वह एकदम बोल उठी कि अगर किसी ने पहले ही पूछ लिया होता तो घर में आग तो न लगती। इसी तरह एक और कहानी है कि किसी नाई ने राजा का कटा हुआ कान देख लिया था। राजा ने उसे मना किया कि यह बात किसी और को न बताए। बताने पर उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, लेकिन नाई को वह बात हज़म नहीं हो पा रही थी। उसके कारण उसका पेट

> **प्रकृति में यही है कि जो जैसा कर्म करेगा, वैसा फल पाएगा, हम दूसरों के लिए कर्म करेंगे-यही हमारा यज्ञ है। यह यज्ञ धर्म संस्कृति का आधार है। वृक्ष अपने फल कभी नहीं खाता। वह अपने संपूर्ण जीवन रस को फल में रख देता है। वह तो पत्थर मारने वाले को भी फल देता है। नदियां अपना सारा पानी खुद ही पीने लग जाएं, वृक्ष अपने फल ख़ुद ही खाने लग जाएं तो दूसरों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। सृष्टि का चक्र ही रुक जाएगा। सबका आधार कर्म है।**

फूल गया था। वह किसी इलाज से ठीक नहीं हुआ। किसी साधू के बताने पर उसने अपनी बात जंगल में जाकर एक बांस के पेड़ को बताई। तब जाकर उसका पेट फूलना बंद हुआ। इसी तरह सारे सुखों के साथ-साथ मानसिक सुख भी आवश्यक है। व्यक्ति का सृष्टि की सत्ता के साथ-साथ जहां ताल-मेल बैठे, उसी में से सेवा, यज्ञ, त्याग की वृत्ति पैदा होती है। यही धर्म है। चारों पुरुषार्थ-धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष-जितनी पद्धतियां चारों सुखों की हैं, वे इसके अंतर्गत आती हैं। व्यक्ति, समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि इन चारों सत्ताओं में एकात्मता है।

कर्म, पुनर्जन्म सबके अंदर एक ही सत्य है-ब्रह्म। एकोहम् द्वितीयो नास्ति। यज्ञ की उस एकात्मता के आधार पर हमारा धर्म टिका है। चतुर्सूत्री के आधार पर हमारे समाज की रचना हुई। ■

- संघ शिक्षा वर्ग, बौद्धिक वर्ग : दिल्ली (13 जून, 1958)

उत्तर प्रदेश से भाजपा विधायक लोकेंद्र सिंह चौहान की हादसे में मौत

उत्तर प्रदेश के बिजनौर की नूरपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री लोकेन्द्र सिंह चौहान की 21 फरवरी को सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। 45 वर्षीय विधायक श्री लोकेन्द्र के साथ उनके दो गनर, कार चालक व एक भाजपा कार्यकर्ता की भी मौत हो गई। विधायक 'यूपी इन्वेस्टर्स समिट' के लिए बिजनौर से लखनऊ जा रहे थे।

गौरतलब है कि सीतापुर में विधायक श्री लोकेंद्र की गाड़ी एनएच-24 के कमलापुर थाना क्षेत्र के ककैयापारा में अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराते हुए विपरीत दिशा से आ रही एक ट्रक में जा घुसी।

भाजपा विधायक श्री लोकेंद्र सिंह की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व भाजपा अध्यक्ष श्री अमित शाह ने शोक व्यक्त किया और पार्टी व समाज के लिए उनके किए गए योगदान को याद किया।

@narendramodi
मैं लोकेंद्र सिंह जी की मौत से दुखी हूं। समाज और यूपी में भाजपा के निर्माण में उनका योगदान हमेशा ही याद किया जाएगा। इस भयंकर दु:ख की घड़ी में मेरी भावनाएं और समर्थन उनके परिवार के साथ है।

@AmitShah
मैं हमारी पार्टी के विधायक लोकेंद्र सिंह की मौत से दु:खी हूं। उन्होंने समर्पण से समाज और पार्टी की सेवा की है। उनका निधन पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है।

@myogiadityanath
जनपद बिजनौर के नूरपुर से भाजपा विधायक श्री लोकेंद्र चौहान जी के निधन पर पर दु:ख पहुंचा। श्री लोकेंद्र चौहान जी के निधन से पार्टी ने एक प्रतिबद्ध नेता खो दिया है। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति एवं परिजनों को संबल देने की प्रार्थना करता हूं।

जीवन परिचय

बिजनौर के स्योहारा थाना क्षेत्र के गांव आलमपुर निवासी विधायक श्री लोकेन्द्र सिंह चौहान का राजनीतिक सफर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् से प्रारम्भ हुआ था। उनकी शिक्षा धामपुर के आरएसएम डिग्री कालेज में हुई। वह वर्ष 1990 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् में सक्रिय रहे। 2001 में भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रहे। 2003 में भाजपा के जिला महामंत्री रहे। वह 2009 में भाजपा जिलाध्यक्ष रहे। 2012 में नूरपुर विधानसभा सीट सृजित होने के बाद वह भाजपा से विधायक बने। इसी सीट पर वह दूसरी बार चुनाव जीत गए। विधायक श्री लोकेंड विधानसभा कमेटी के कोषाध्यक्ष भी रहे। ■

राजस्थान से भाजपा विधायक कल्याण सिंह चौहान नहीं रहे

राजस्थान से भाजपा विधायक श्री कल्याण सिंह चौहान का लम्बी बीमारी के बाद 21 फरवरी को निधन हो गया। 18 नवम्बर 1959 को जन्मे श्री कल्याण सिंह पिछले एक वर्ष से कैंसर से पीड़ित थे, उनका उदयपुर के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सहित मंत्रिमण्डल के कई सदस्यों ने नाथद्वारा जाकर श्री कल्याण सिंह के शव पर पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यपाल श्री कल्याण सिंह ने विधायक के निधन पर शोक जताया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री अशोक परनामी ने भी श्री सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया।

गौरतलब है कि नाथद्वारा से दूसरी बार विधायक रहे श्री कल्याण सिंह साल 2008 के विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री सीपी जोशी को हराकर जीत दर्ज की थी। ■

'खेत खलिहान से गुजरता है देश की समृद्धि का रास्ता'

भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने 31 जनवरी को नई दिल्ली स्थित भाजपा केन्द्रीय कार्यालय में एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में देश भर से 110 प्रतिनिधि शामिल हुए। 25 राज्यों से भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश मीडिया एवं सोशल मीडिया प्रभारियों के साथ ही किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने कार्यशाला में हिस्सा लिया। कार्यशाला का उद्‌घाटन भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन श्री रामलाल एवं किसान मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र सिंह मस्त ने किया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने मार्गदर्शन किया। संचालन राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी श्री राकेश सिंह ने किया।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि केन्द्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग एवं जहाजरानी मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा कि कि नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने गांव, गरीब और किसान को सरकारी नीतियों के केन्द्र लाया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि किसान मोर्चा के कार्यकर्ता सरकार की किसान संबंधित नीतियों - कार्यक्रमों को जनता के बीच में ले जाएं। आजाद भारत में पहली बार गांव गरीब और किसान की चिंता करने वाली सरकार है। नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार की नीतियां और कार्यक्रम इसकी गवाही देते है।

श्री गडकरी ने इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर जोर देते हुए कहा कि हमें नए नए प्रयोगों की तरफ ध्यान देना होगा। हमारे पास खेतों में पेट्रोल डीजल का विकल्प पैदा करने की क्षमता है। कल तक हमारी इस बात पर कोई विश्वास नहीं करता था। एथनाल से नागपुर में बस चल रही है। अन्य परिवहन के साधन भी एथनाल से चलाने का प्रयोग सफल रहा है। हमें इन प्रयोगों की तरफ अपने आपको ले जाना है। गडकरी जी ने कहा कि मात्र मौसमी फसल पर किसान निर्भर न करके वैकल्पिक आय के साधन जैसे बांस, एथनाल, कचरा प्रबंधन से ऊर्जा पैदा करके किसान अपनी आय को कई गुना बढ़ा सकते हैं।

देशभर से आए किसान मोर्चा के मीडिया और सोशल मीडिया प्रभारियों का मार्गदर्शन करते हुए भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री रामलाल ने कहा कि किसान मोर्चा सोशल मीडिया और अपने कार्यकर्ताओं के जरिए केन्द्र सरकार और भाजपा की राज्य सरकार की कृषि योजनाओं को खेत खलिहान तक पहुंचाए। श्री रामलाल ने कहा कि किसान मोर्चा कों किसानों और पार्टी के बीच पुल का काम करना है।

किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र सिंह मस्त ने कहा कि हमें किसानों से संवाद कार्यक्रम के जरिए मोदी सरकार की उपलब्धियों को किसानों के बीच ले जाना चाहिए। हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री

और किसान मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनकड़ ने भाजपा की राज्य सरकारों की कृषि नीतियों और कार्यक्रमों की जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय किसान मोर्चा द्वारा आयोजित मीडिया कार्यशाला के द्वितीय सत्र की अध्यक्षता मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री नरेश सिरोही और संचालन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री शैलेंद्र सेंगर ने किया। दूसरे सत्र के मुख्य वक्ता केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधामोहन सिंह ने केन्द्र सरकार के किसानों के कल्याण के लिए अब तक किए गए प्रयासों की विस्तृत जानकारी देश भर से आए प्रतिनिधियों को दिया। उन्होंने कहा कि अब तक देश भर में 1000 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं बना दी गईं हैं। नरेन्द्र मोदी की सरकार ने देशी गोवंश के संवर्द्धन के लिये रोडमैप तैयार किया। कृषि राज्यमंत्री श्री गजेंद्र शेखावत ने कहा कि किसानों को अपना दृष्टिकोण अब उत्पादन आधारित से आय आधारित बनाने की दिशा में मोड़ना होगा। इससे ही किसानों की खुशहाली सुनिश्चित होगी। श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने किसान मोर्चा की वेबसाइट www.bjpkisanmorcha.org का लोकार्पण किया। किसान मोर्चा के सोशल मीडिया और आईटी संयोजक श्री अनिरूद्ध ने वेबसाइट और किसान मोर्चा के फेसबुक पेज @bjpkm4kisan और ट्वीटर @bjpkm4kisan के बारे में जानकारी दी।

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री शैलेन्द्र सेंगर ने प्रदेशों से आए हुए प्रदेश अध्यक्षों से किसान मोर्चा के कार्यक्रमों की जानकारी ली। भाजपा के सोशल मीडिया और आईटी प्रमुख श्री अमित मालवीय ने प्रजंटेशन के जरिए केन्द्र सरकार की कृषि योजनाओं को समझाया। कमल संदेश के कार्यकारी संपादक श्री शिवशक्ती बक्शी ने मीडिया प्रबंधन और भाजपा सरकार की कृषि योजनाओं पर अपनी बात रखी। कार्यशाला को राष्ट्रीय मंत्री श्री दुष्यंत लाकड़ा, राष्ट्रीय सह मीडिया प्रभारी आचार्य एस के मिश्र ने भी संबोधित किया। दिन भर चले इस कार्यशाला में अतिथियों और प्रतिभागियों का राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री श्री रवीन्द्र कुमार सिंह ने धन्यवाद दिया। ■

प्रधानमंत्री की फिलिस्तीन, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान की सफल यात्रा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 9 से 12 फरवरी के दौरान फिलिस्तीन, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और ओमान की चार दिवसीय सफल यात्रा की। इस यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते तो हुए ही, साथ ही इन देशों के साथ भारत के संबंध और भी घनिष्ठ हुए। गौरतलब है कि यह फिलिस्तीन यात्रा किसी भारतीय प्रधानमंत्री की प्रथम यात्रा थी और यूएई यात्रा श्री मोदी की दूसरी तथा ओमान की श्री मोदी प्रथम यात्रा थी।

फिलिस्तीनः स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में छह समझौता

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति श्री महमूद अब्बास के बीच 10 फरवरी को एक द्विपक्षीय बैठक के बाद स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में छह समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में बेथलेहम के बेत सहौर में 30 लाख डॉलर की लागत से एक भारत-फिलिस्तीन सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना तथा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पांच करोड़ डॉलर के लागत की 'तुराथी' नामक भारत-फिलिस्तीन केंद्र का निर्माण प्रमुख है। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति श्री अब्बास ने शांति प्रक्रिया बरकरार रखने में भारत से समर्थन मांगा।

इस मौके प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि मैंने प्रेसिडेंट अब्बास को भरोसा दिया है कि भारत फिलिस्तीन के लोगों के हितों के लिए किए गए वादे के प्रति प्रतिबद्ध है। भारत और फिलिस्तीन के रिश्तों की हमेशा परीक्षा होती रही है। फिलिस्तीन हमेशा हमारी विदेश नीति में टॉप पर रहा है। श्री मोदी ने बताया कि वह खुश हैं कि स्टूडेंट एक्सचेंज एग्रीमेंट में इस साल से 50 से बढ़ाकर संख्या 100 कर दी गई है।

संयुक्त अरब अमीरात के साथ हुए 5 समझौते

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में अबूधाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के शहजादे और शाही परिवार के अन्य सदस्यों ने उनकी अगवानी की। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया। श्री मोदी ने हवाई अड्डे पर स्वागत के लिए शहजादे का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उनकी यात्रा का भारत संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) संबंध पर सकारात्मक असर पड़ेगा।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के शहजादे श्री मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात कर कई मुद्दों पर बातचीत की। इस मौके पर दोनों देशों के बीच 5 करारों पर हस्ताक्षर हुए। इनमें इंडियन ऑयल के नेतृत्व वाले कंपनी समूह को अपतटीय तेल सुविधा में 10 फीसदी हिस्सेदारी देने का करार भी शामिल है।

श्री मोदी ने अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर का शिलान्यास किया

श्री मोदी ने विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर का शिलान्यास किया। 55000 वर्ग मीटर भूमि में बनने वाला यह मंदिर

पश्चिम एशिया में पत्थरों से बना पहला हिंदू मंदिर होगा, जिसे बीएपीएस संस्था द्वारा बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने यूएई में रह रहे भारतीयों को संबोधित भी किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा, 'शायद कई दशकों के बाद भारत का खाड़ी देशों के साथ इतना व्यापक और गहरा नाता बना है।'

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं मंदिर निर्माण से जुड़े हुए सबसे आग्रह करूंगा कि यहां के शासकों ने भारत के प्रति इतना सम्मान जताया है। भारत की सांस्कृतिक परंपराओं का इतना गौरव किया है ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमसे कोई चूक न रह जाए, कोई गलती न हो जाए।

श्री मोदी ने कहा कि मानवता के उदात्त आदर्शों और विचारों को कहीं कोई खरोंच न आ जाए इसकी जिम्मेवारी इस मंदिर निर्माण से जुड़े हुए और मंदिर से जुड़ने वाले भावी भक्तों के लिए भी ये बहुत अनिवार्य रहेगी। ऐसी मेरी आप सबसे अपेक्षा है। दुबई में सामुदायिक अभिनन्दन के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भारत इस बात के लिए गर्व करता है कि खाड़ी के देशों में 30 लाख से भी अधिक भारतीय समुदाय के लोग यहां की विकास यात्रा में भागीदार हुए है। मैं खाड़ी के देशों का ह्दय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उन्होंने हमारे देश के 30 लाख से अधिक लोगों को यहां भारत के बाहर जैसे उनका दूसरा घर हो उस प्रकार का उत्तम वातावरण दिया है।

श्री मोदी ने कहा कि आज देश विकास की नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है। ये भारत के लिए सम्मान का विषय है कि आज एक विश्व स्तर के समिट में भारत को विशेष सम्मान दिया गया है। मुझे वहां संबोधन करने के लिए निमंत्रण मिला है। यहां आप लोगों के लिए भारत की जानकारी पाना मुश्किल नहीं है। अगर मैं कोई दो चीज बोलूंगा तो आप दस चीज बताएगें इतनी आपको भारत की जानकारी है और एक प्रकार से यहां पर लघु भारत बसता है।

उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान में कोई कोना ऐसा नहीं होगा कि जिसका प्रतिनिधित्व यहां नहीं होगा और इसलिए भारत तेजी से बदल रहा है। सवा सौ करोड़ भारतीय अपने सपनों को पूरा करने के लिए किस आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहे हैं। ये आप भली-भांति अनुभव कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री श्री मोदी, फिलस्तीन के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित

द्विपक्षीय बैठक के बाद फिलस्तीनी राष्ट्रपति श्री महमूद अब्बास ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान 'ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलस्तीन'से सम्मानित किया। यह विदेशी राष्ट्राध्यक्षों/ शासनाध्यक्षों या इसके समकक्ष पद पर बैठे लोगों को दिया जाने वाला फिलिस्तीन का सर्वोच्च सम्मान है। स्टेट ऑफ फिलिस्तीन के ग्रैंड कॉलर से सम्मानित किए जाने पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा, 'यह भारत का सम्मान है और फिलिस्तीन की मित्रता का प्रतीक। मैं सभी भारतीयों की ओर से इसके लिए धन्यवाद देता हूं।'

भाजपा अध्यक्ष श्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को 'ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलस्तीन' सम्मान से नवाजे जाने पर बधाई दी। श्री शाह ने कहा कि यह सम्मान पूरे देश और भाजपा के लिए 'बड़े गर्व और सम्मान' की बात है। गौरतलब है कि श्री शाह ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री को यह बधाई दी।

ओमान के साथ 8 समझौतों पर हस्ताक्षर

प्रधानमंत्री श्री मोदी अपनी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव में ओमान पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को ओमान के सुल्तान श्री कबूस बिन साद अल साद के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इसके अलावा प्रधानमंत्री श्री मोदी ओमान के सुल्तान के अलावा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ काउंसिल श्री सैयद फयद बिन महमूद अल सैयद के साथ भी मुलाकात की।

यात्रा के दौरान श्री नरेंद्र मोदी ने ओमान के सुल्तान से कई विषयों पर चर्चा की और दोनों देशों के बीच रक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग सहित 8 समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए। इस दौरान व्यापार और निवेश, ऊर्जा ,रक्षा, सुरक्षा ,खाद्य सुरक्षा और क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत हुई।

ओमान के साथ हुए समझौते

- दीवानी और व्यावसायिक मामलों में कानूनी और न्यायिक सहयोग के लिए समझौता
- राजनयिक, विशेष, सेवा और अधिकारिक पासपोर्ट धारकों को वीजा में आम सहमति से छूट के लिए समझौता
- स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग के लिए सहमति पत्र
- अंतरिक्ष के शांतिपूर्वक प्रयोग में सहयोग के लिए सहमति पत्र
- भारत में विदेश मंत्रालय के अंतर्गत विदेश सेवा संस्थान और ओमान राजनयिक संस्थान के बीच सहयोग पर सहमति पत्र
- ओमान के नेशनल डिफेंस कालेज और भारत के रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान के बीच शैक्षणिक सहयोग पर सहमति पत्र
- भारत और ओमान के बीच पर्यटन सहयोग के क्षेत्र में सहमति पत्र
- सैन्य सहयोग पर सहमति पत्र के लिए संलग्नक

आज अपने सामने मिनी इंडिया को देख रहा हूं: नरेंद्र मोदी

मस्कट, ओमान में कम्युनिटी इवेंट के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 11 फरवरी को को कहा कि आज हर भारतीय न्यू इंडिया के संकल्प को पूरा करने के लिए काम कर रहा है। हम एक ऐसे भारत के निर्माण की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां गरीब से गरीब व्यक्ति को भी आगे बढ़ने के समान अवसर मिलें, जहां गरीब से गरीब व्यक्ति भी सपने देख सके, उन्हें पूरा कर सके।

उन्होंने कहा कि आज अपने सामने, मैं मिनी इंडिया को देख रहा हूं। देश के अलग-अलग कोनों से आए भारतीय, अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने वाले भारतीय, एक भव्य तस्वीर का निर्माण कर रहे हैं। ■

बड़ी संख्या में निवेशकों की भागीदारी है परिवर्तन का संकेत: नरेन्द्र मोदी

4.28 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी निवेश के प्रस्ताव

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 21 फरवरी को उत्तर प्रदेश निवेशक सम्मेलन-2018 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि जब परिवर्तन होता है तो वह प्रत्यक्ष रूप से दिखता है। उत्तर प्रदेश में इतने बड़े शिखर सम्मेलन का आयोजन और इसमें बड़ी संख्या में निवेशकों की भागीदारी अपने आप में परिवर्तन का संकेत है। उन्होंने कम समय में खुद को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने के लिए राज्य को बधाई दी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य अपार संसाधनों और क्षमताओं से परिपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कृषि इसकी सबसे बड़ी ताकत है। श्री मोदी ने मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को राज्य के नकारात्मक माहौल को सकारात्मकता और उम्मीद में बदलने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न क्षेत्रों के लिए सही और सक्षम नीतियां बना रही हैं। राज्य सरकार युवाओं, महिलाओं और किसानों से किये गये वायदों को पूरा करने के प्रति गंभीर है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रॉडक्ट की अवधारणा पर काम कर रही है। इस योजना को केंद्र की स्किल इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी तमाम योजनाओं से लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से कृषि क्षेत्र में होने वाली बर्बादी को रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती होने के कारण राज्य में इथेनोल उत्पादन की अपार क्षमता है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक रक्षा औद्योगिक गलियारा बनाया जाएगा, जिससे बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास में मदद मिलेगी।

केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा कि यह समिट परिवर्तन की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि सरकारों के बदलने से किसी प्रान्त की स्थिति में भी परिवर्तन हो, यह जरूरी नहीं। लेकिन वर्तमान सरकार ने राज्य की स्थिति में बदलाव लाने का इतिहास रचा है और यहां से आर्थिक स्थिति में परिवर्तन की शुरुआत हो रही है। उन्होंने कहा कि आज के समय में निवेशक के सामने यह विकल्प होता है कि वह निवेश को किस प्रान्त व किस देश में करे। निवेशकों को आकर्षित कर विकास की धारा को दिशा दी जा सकती है। निवेश से आर्थिक गतिविधि बढ़ती है, जिससे रोजगार में वृद्धि होती है और फिर राजस्व बढ़ता है। राजस्व बढ़ने से सरकार के संसाधन बढ़ते हैं। इन संसाधनों के बढ़ने से गरीबों की सेवा करने में मदद मिलती है। सोशल व फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोत्तरी होती है। इन सबसे आकर्षित होकर निवेशक और पूंजी निवेश करता है और फिर यह विकास का चक्र चलता रहता है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने 'यू.पी. इन्वेस्टर्स समिट' के आयोजन की सफलता की चर्चा करते हुए कहा कि इसमें 10 देशों, 110 कम्पनियों, 100 मीडिया हाउसेज़ और 600 प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें 32 सत्रों के दौरान लगभग 120 वक्ताओं ने अपने विचार रखे। समिट में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 10 फोकस सेक्टर्स-एग्रो और फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, हैण्डलूम एण्ड टेक्सटाइल, एम.एस.एम.ई., आईटी/आईटीईएस एण्ड स्टार्टअप, एलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, फिल्म, टूरिज्म, सिविल एविएशन और रिन्यूएबिल एनर्जी आदि के सम्बन्ध में व्यापक चर्चा हुई। साथ ही, डिफेन्स और एयरोस्पेस पर भी विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया। इस दौरान 1,045 एमओयू हस्ताक्षरित हुए और 4.28 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए।

मुख्यमंत्री ने समिट में प्रतिभाग कर रही पार्टनर कण्ट्रीज-जापान, थाईलैण्ड, नीदरलैण्ड, फिनलैण्ड, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया और मारिशस के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन देशों द्वारा निवेश करने से प्रदेश में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा डिफेन्स कारिडोर के सम्बन्ध में की गई घोषणा को प्रदेश के लिए एक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इसमें 20 हजार करोड़ रुपए का निवेश होगा, जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निवेश की सम्भावनाएं बढ़ेंगी। उन्होंने उत्तर प्रदेश को सबसे उपयुक्त निवेश स्थल की संज्ञा देते हुए कहा कि कानून व्यवस्था सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से बेहतर हुई है। उन्होंने कहा कि सिंगल विण्डो पोर्टल को डिजिटल क्लीयरेन्स के साथ जोड़े जाने से अब लालफीताशाही और प्रशासनिक विलम्ब का स्थान नहीं रहेगा। राज्य ने 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस' के क्षेत्र में एक लम्बी छलांग लगाई है। उत्तर प्रदेश में इस समिट के बाद एक नए युग की शुरुआत हो चली है। ■

परीक्षा के लिए मोदी मंत्र

| कैलाश विजयवर्गीय |

श्री नरेंद्र मोदी को हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री और अब देश के प्रधानमंत्री के तौर पर देखा है। एक राजनीतिक हस्ती के तौर पर उनमें बहुत खूबियां हैं। ऐसी खूबियां बहुत से राजनीतिज्ञों में रही हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी, जो उन्हें खास बनाती है, वह है देश और समाज के लिए बिना राजनीतिक इच्छा के काम करना। समाज के हर वर्ग के लिए वे लगातार परिश्रम करते हैं। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पर चर्चा करते हुए उन्होंने विद्यार्थियों को जो जीने का मंत्र दिया, वह हम सभी के लिए महत्व का है। परीक्षा की तैयारियों में लगे हर विद्यार्थी को तनाव रहता है। विद्यार्थी को ही नहीं उसके पूरे परिवार को परीक्षा में अच्छे अंक लाने की चिंता रहती है। बच्चों को तमाम सलाह दी जाती है। घूमने-फिरने पर रोक लगा जाती है। परिवारों में टीवी चलने बंद हो जाते हैं। शिक्षक और परिवार का हर सदस्य बस पढ़ो-पढ़ो की रट लगाये रहते हैं। मोदीजी ने परीक्षा के तनाव दूर करने के लिए छात्रों को जो मंत्र दिया, उससे एक नई राह मिली है।

हमने टीवी चैनलों पर देखा भी कि मोदीजी एक प्रधानमंत्री की तरह नहीं, बल्कि एक शिक्षक और अभिभावक की भूमिका में दिखाई दिए। प्रतिस्पर्धा, आत्मविश्वास, एकाग्रता की चर्चा करते हुए अभिभावकों को भी बताया किस तरह बच्चों में अलग भावनाओं का समावेश करें। अगले लोकसभा चुनाव को लेकर पूछे गए एक बच्चे के सवाल पर उन्होंने प्रशंसा करते हुए बड़ी सहजता से जवाब दिया कि चुनाव के लिए कोई काम नहीं करता। यह सही है कि राजनीति में रहते हुए भी मोदीजी राजनीतिज्ञों जैसा व्यवहार नहीं करते हैं। वे कर्मयोगी हैं, उनके विचार हमें हमेशा नई राह दिखाते हैं। मोदीजी ने बताया भी कि बात मेरी परीक्षा की तैयारी की तो मैं चुनाव को ध्यान में रखकर काम नहीं करता हूं। चुनाव तो आएंगे-जाएंगे। मेरे पास जितना समय, शक्ति, बूता है और जितनी दिमागी ताकत होती है, वह देशवासियों के लिए खपाता हूं। चुनाव परिणाम को लेकर काम नहीं करता हूं। उनकी यह बात बहुत गौर करने वाली है कि 'वैसे तो मैं राजनीतिक व्यवस्था में हूं, लेकिन मन, मस्तिष्क और स्वभाव से राजनीति में नहीं हूं। मेरे नेचर में यह नहीं है। मेरे नेचर में हर समय कुछ करने की ललक बनी रहती है। अगर एक राजनीतिज्ञ के तौर पर या गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए और अब प्रधानमंत्री के कार्यों को देखे तो उनका एक ही मंत्र होता है कि हर समय अपने-अपने काम करते रहो, चुनाव हो या कोई परीक्षा कभी तनाव नहीं होगा। हम सभी जानते हैं कि मेधावी छात्र परीक्षा आने पर पढ़ाई नहीं करते हैं, बल्कि वे नई कक्षा में आते ही पढ़ाई पर पूरा ध्यान देते हैं।

मोदीजी से हमने यही सीखा है कि चुनाव आने पर अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय होने के बजाय हर समय लोगों के बीच जाते रहो। उनके सुख-दुख में भागीदार बनो। यही उनकी सफलता का मंत्र है। बच्चों को एक शिक्षक के तौर पर उन्होंने जो मंत्र दिया, उससे छात्रों को परीक्षा के साथ जीवन को नए तरीक से देखने की प्रेरणा मिली है। एक परिवार के बड़े सदस्य की तरह उन्होंने अभिभावकों को भी सलाह दी कि बच्चों को स्टेटस सिंबल से मत जोड़ो। हर किसी को भगवान ने कुछ न कुछ करने की परम शक्ति दे रखी है। उसे पहचानो और बच्चों को आगे बढ़ने दो। कोई काम करने के लिए उन्होंने एकाग्रता, शरीर, मन, आत्मा और बुद्धि को जोड़ने की सलाह दी। जब इन सबका मिलन होता है तो काम ठीक हो जाता है। परीक्षा के दौरान तनाव है तो उन्होंने एकाग्रता के लिए बच्चों को योग करने की सलाह भी दी। प्रतिस्पर्धा की भावना के बजाय उन्होंने छात्रों को अनुस्पर्धा यानी खुद से स्पर्धा करने की सलाह देकर तमाम झंझटों से बचने का रास्ता दिखाया है। उनके इस मंत्र को अपनाने से परीक्षा के तनाव तो दूर होंगे ही, साथ ही हमें नई राह पर चलने की प्रेरणा मिलेगी। ■

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं)

विधानसभा चुनावों पर विशेष

'जनता ने राज्य के विकास के लिए परिवर्तन करने का मन बना लिया है'

उत्तर-पूर्व के तीन राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नगालैंड में विधानसभा चुनावों का दौर जारी है। इन तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव दो चरणों में संपन्न होने हैं। पहले चरण में 18 फरवरी को त्रिपुरा में मतदान हुए। दूसरे चरण में 27 फरवरी को मेघालय और नागालैंड में मत पड़ने हैं। 3 मार्च को तीनों राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के लिए गिनती होगी और परिणामों की घोषणा की जाएगी। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर-पूर्व के राज्यों में भी अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रही है।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 12 फरवरी को होटल सोनार तोरी, अगरतला में प्रेस वार्ता को संबोधित किया और त्रिपुरा की बदहाली के लिए राज्य की माणिक सरकार की वामपंथी सरकार पर जमकर प्रहार किया।

श्री शाह ने कहा कि त्रिपुरा की जनता ने राज्य में परिवर्तन करने का मन बना लिया है और अब तक के चुनाव प्रचार एवं राज्य के प्रत्येक विधानसभा के विश्लेषण के पश्चात् यह स्पष्ट है कि त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में सीपीएम सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश है। 35 साल के वामपंथी शासन में त्रिपुरा विकास की दौड़ में काफी पिछड़ गया है। उन्होंने कहा कि देश में जहां-जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां हर क्षेत्र में तेज गति से विकास हुआ है लेकिन त्रिपुरा में सीपीएम सरकार के कारण विकास नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि इस कारण सीपीएम नेतृत्व और उसके कैडर में घोर निराशा का माहौल है और अब अपने मूल स्वभाव के अनुरूप सीपीएम हिंसा के रास्ते पर तेज गति से जाता हुआ दिखाई दे रहा है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कल ही भारतीय जतना पार्टी ने त्रिपुरा के लिए अपना विजन डॉक्युमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर हर घर में एक रोजगार का प्रावधान किया जाएगा, हर घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाया जाएगा, युवाओं को फ्री स्मार्टफोन दिए जायेंगे, सरकारी कर्मचारियों के लिए चौथे वेतन आयोग की जगह सातवां वेतन आयोग लागू किया जाएगा, न्यूनतम मजदूरी को मोदी सरकार की तर्ज पर 340 रुपये प्रतिदिन किया जाएगा, केंद्र सरकार की फ्री हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को अच्छे तरीके से लागू किया जाएगा और दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर त्रिपुरा की बदहाल क़ानून-व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा की जनता से यह भी वादा किया है कि रोजवैली चिटफंड एवं अन्य चिटफंड घोटालों में त्रिपुरा की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई को जिसने भी हजम किया है, उसे क़ानून के दायरे में लाकर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी के कारण राज्य में जो 10 हजार से ज्यादा शिक्षक अपनी नौकरी गंवा बैठे हैं, उनके लिए भी संवैधानिक रास्ता निकालकर उनकी परिमार्जन की व्यवस्था की जायेगी। उन्होंने कहा कि हमने राज्य की जनता से यह भी वादा किया है कि त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गठित होने पर हर विधान सभा क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज खोला जाएगा और लड़कियों को ग्रेजुएशन तक की शिक्षा मुफ्त उपलब्ध कराई जायेगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने इस बार के बजट में किसानों को अपनी लागत से डेढ़ गुना ज्यादा समर्थन मूल्य देने का जो एलान किया है, उसे वैज्ञानिक तरीके से लागू करने के लिए त्रिपुरा की भारतीय जनता पार्टी सरकार एक मैकेनिज्म डेवलप करेगी।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि माणिक सरकार की सीपीएम सरकार त्रिपुरा का विकास कर ही नहीं सकती, यह केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। उन्होंने कहा कि जब कम्युनिस्ट पार्टी त्रिपुरा में सत्ता में आई तो राज्य में केवल 25 हजार लोग बेरोजगार थे, लेकिन सीपीएम सरकार की 25 साल की उपलब्धि है कि आज राज्य में 7,33,000 युवा बेरोजगार हैं। उन्होंने कहा कि माणिक सरकार की सरकार में त्रिपुरा की क़ानून-व्यवस्था बद से बदतर हो गई है, सीपीएम कैडरों के इशारे पर राज्य की पुलिस काम करती है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में त्रिपुरा काफी आगे है। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में हर दिन लगभग 5 अपराध महिलाओं के खिलाफ होते हैं, जिसमें से 2 बलात्कार के मामले होते, हम त्रिपुरा की इस स्थिति में परिवर्तन लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा की जनता अराजकता के माहौल से बाहर निकलने के लिए त्रिपुरा की जनता भारतीय जनता पार्टी की ओर आशा से देख रही है। उन्होंने कहा कि मुझे यह कहने में कोई संदेह नहीं कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में त्रिपुरा देश का 20वां एनडीए शासित प्रदेश बनने जा रहा है, इसका हम सबको भरोसा है। ■

'कांग्रेस सरकार ने 10 वर्षों के कार्यकाल में भ्रष्टाचार करने के अलावे कोई और काम किया ही नहीं है'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 16 फरवरी को जोवई और शिलांग (मेघालय) में आयोजित विशाल जनसभाओं को संबोधित किया और मेघालय के विकास के लिए राज्य की भ्रष्टाचारी कांग्रेस सरकार को जड़ से उखाड़ कर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की अपील की।

श्री शाह ने कहा कि मुकुल संगमा के नेतृत्व मेघालय की कांग्रेस ने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में भ्रष्टाचार करने के अलावा कोई और काम किया ही नहीं है। उन्होंने कहा कि क्या मेघालय की जनता राज्य में ऐसी सरकार चाहती है, जो प्रदेश के विकास के लिए मोदी सरकार द्वारा भेजी गई राशि को जनता की भलाई के बजाय गबन कर जाती हो या फिर ऐसी सरकार चाहिए जो मेघालय को दुनिया का सबसे आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि 10 वर्षों में मेघालय के गांवों में न तो बिजली पहुंच पाई, न लोगों को शुद्ध पीने का पानी मिला और न ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य की ही समुचित व्यवस्था ही हो पाई।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि यहां जयंतिया हिल्स में कोयले का बहुत बड़ा कारोबार होता था, लेकिन कांग्रेस की मुकुल संगमा सरकार के करप्शन के कारण एनजीटी ने खदानों को बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि इसी तरह देश में कई खदानों पर एनजीटी ने रोक लगा दी थी, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सभी खदानों पर से एनजीटी की रोक हटी है और माइनिंग शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि मैं मेघालय की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि यदि मेघालय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो ट्रांसपेरेंट तरीके से इन सारी खदानों को शुरू कर जयंतिया हिल्स इलाके के युवाओं को रोजगार मिले, ऐसी व्यवस्था करेगी।

श्री शाह ने कहा कि 10 साल तक मेघालय की कांग्रेस सरकार ने मेघालय की गरीब जनता के पैसे करप्शन में खर्च करने के अलावे कोई और काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि मुकुल संगमा सरकार के घोटालों की एक लंबी सूची है - टीचर्स की भर्ती में घोटाले की बात हो, 2012 का माइनिंग स्कैम हो, शुगर स्कैम हो, पुलिस रिक्रूटमेंट घोटाला हो या अन्य घोटाले। उन्होंने कहा कि मैं आज इस मंच से मेघालय के मुख्यमंत्री को पूछना चाहता हूं कि इतने सारे घोटालों के बाद मेघालय की जनता आपको वोट क्यों देगी?

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मुकुल संगमा सवाल पूछते हैं कि चार सालों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने मेघालय के लिए क्या किया? उन्होंने कहा कि जब केंद्र में और राज्य में, दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त कांग्रेस की यूपीए सरकार ने 13वें वित्त आयोग के दौरान

मेघालय को जहां केवल 5800 करोड़ रुपये दिए थे, वहीं 14वें वित्त आयोग में मोदी सरकार ने मेघालय के लिए लगभग 25,400 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त स्वच्छ भारत अभियान के लिए 4 करोड़, ट्रांसपोर्टेशन के लिए 46 करोड़, अमृत मिशन के लिए 80 करोड़, टूरिज्म के लिए 100 करोड़ और सड़कों के लिए अलग से सैकड़ों करोड़ रुपये की राशि दी है। कुल मिलाकर मेघालय को विकास के अन्य प्रोजेक्ट्स के लिये लगभग 580 करोड़ रुपये देने का काम मोदी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि मेघालय में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से लगभग 30 हजार गरीब महिलाओं को लाभ पहुंचा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने इस बार के बजट में देश के लगभग 10 करोड़ परिवारों अर्थात् लगभग 50 करोड़ लोगों को पांच लाख रुपये सालाना हेल्थ इंश्योरेंस देने का एलान किया है, इससे पूर्वोत्तर के गरीब लोगों को आसानी से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि मेघालय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर राज्य के हर जिले में एकलव्य रेजीडेंसी स्कूल खोले जायेंगे।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसके तहत पूर्वोत्तर में रोड कनेक्टिविटी, आईटी कनेक्टिविटी, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट और टूरिज्म डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के साथ-साथ युवाओं को यहीं पर रोजगार मिले, इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन कांग्रेस की मुकुल संगमा सरकार राज्य के विकास के प्रति उदासीन है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राज्य की जनता का आह्वान करते हुये कहा कि आप एक बार मेघालय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन कीजिये, केंद्र की श्री नरेन्द्र मोदी सरकार और राज्य की भाजपा सरकार मिल कर मेघालय को दुनिया का सबसे आकर्षक डेस्टिनेशन बनायेगी और मेघालय को देश का एक विकसित राज्य बनायेगी। ■

भाजपा के नवनिर्मित केंद्रीय कार्यालय भवन का उद्घाटन

भाजपा के रग-रग में देशभक्तिः नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 18 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी के नए मुख्यालय का उद्घाटन किया। डेढ़ साल के रिकार्ड टाइम में भाजपा का मुख्यालय बन कर तैयार हुआ है, जिसके लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह और उनकी टीम की जम कर प्रशंसा भी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा ऐसी पार्टी है, जो अपने मूलभूत आदर्शों से कभी भी नहीं लड़खड़ाई। उन्होंने कहा कि भाजपा के रग-रग में लोकतंत्र और वह देशभक्ति से परिपूर्ण है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वश्री लालकृष्ण आडवाणी, डॉ. मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, केन्द्रीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज एवं भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री रामलाल के साथ दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित पार्टी मुख्यालय का उद्घाटन किया। 32 साल के बाद भाजपा का मुख्यालय लुटियंस दिल्ली के 11, अशोक रोड से उठ कर 6 ए, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा - मैं अमित भाई और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि समय सीमा में कार्यालय का निर्माण हुआ। उन्होंने कहा कि यह काम बजट की व्यवस्था से नहीं होता, यह तब होता है जब सपना हो और काम करने का जज्बा हो तब जाकर यह काम समय पर पूरे होते हैं। प्रधानमंत्री ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह की तारीफ करते हुए कहा कि इसके लिए टीम स्पिरिट होनी चाहिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में संगठन टोली ने इस काम को बखूबी निभाया है। उन्होंने कहा कि जनसंघ और भाजपा के नेता आजादी के बाद सभी प्रमुख जन आंदोलनों में सबसे आगे रहे। श्री मोदी ने कहा - हमारी पार्टी राष्ट्र भक्ति के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पार्टी के नए मुख्यालय का उद्घाटन करते हुए कहा कि लोकतंत्र उनकी पार्टी के रग-रग में है, जो उसे सभी सहयोगी दलों को सफलतापूर्वक साथ लेकर चलने में सक्षम बनाता है। उन्होंने कहा- भाजपा और इसकी पूर्ववर्ती जनसंघ ने राष्ट्रहित में स्वतंत्रता के समय से सभी आंदोलनों का नेतृत्व किया है। ■

अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 1,70,000 स्क्वायर फीट में फैला भाजपा का यह केन्द्रीय कार्यालय दुनिया की सभी राजनीतिक पार्टियों के कार्यालय में सबसे बड़ा है। यहां से पार्टी के प्रदेश कार्यालय और जिला कार्यालयों के साथ सीधे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये संपर्क साधा जा सकता है। इस कार्यालय में आधुनिक आईटी सेल, सोशल मीडिया सेल और मीडिया के लिए सभी सुविधाओं के साथ बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया गया है। प्रेस के लिये भी लाइव करने की सारी सुविधाएं यहां उपलब्ध हैं। ■

भाजपा एक नए भारत के निर्माण के लिए राजनीति में है: अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 18 फरवरी को नई दिल्ली स्थित भाजपा के नवनिर्मित केंद्रीय कार्यालय (6A, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग) भवन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी का यह नवीन केन्द्रीय कार्यालय करोड़ों कार्यकर्ताओं के समायोजन से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के न्यू इंडिया की परिकल्पना को साकार करने में सफल होगा, ऐसा मुझे भरोसा है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत शुभ और महत्वपूर्ण है, क्योंकि जन संघ की स्थापना से लेकर आज आज तक के पार्टी कार्यकर्ताओं का अपने कार्यालय का स्वप्न आज साकार हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नए केंद्रीय कार्यालय भवन का भूमिपूजन 2016 में रक्षाबंधन के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कर-कमलों द्वारा हुआ था और आज उन्हीं के कर कमलों द्वारा कार्यालय का उद्घाटन भी हो रहा है, यह मेरे लिए काफी हर्ष की बात है। उन्होंने कहा कि अनेकों कार्यकर्ताओं ने इसके लिए अथक परिश्रम किया है, मैं उन सभी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं ।

उन्होंने कहा कि इस देश में हजारों राजनीतिक दल हैं, लेकिन मैं गर्व के साथ भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के नाते यह कह सकता हूं कि संगठन के आधार पर और लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। उन्होंने कहा कि संगठन के आधार पर चलने वाली पार्टी के लिए कार्यालय का बहुत बड़ा महत्त्व होता है। उन्होंने कहा कि 11 प्रकल्पों में से दो प्रकल्प कार्यालय निर्माण एवं कार्यालय आधुनिकीकरण के लिए रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि 2015 में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हमने यह तय किया था कि 694 जिलों में से 635 में हम पार्टी कार्यालय का निर्माण करेंगे। उन्होंने कहा कि आज मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि इन 635 में से 318 कार्यालयों के लिए भूमि खरीद का काम पूरा हो गया है, 125 और कार्यालयों के लिए भूमि खरीद कार्य प्रगति पर है, 192 कार्यालयों का निर्माण पूरा हो चुका है, 100 कार्यलयों का निर्माण प्रगति पर है और एक साल में हम सभी कार्यालयों का निर्माण पूरा हो जाएगा, ऐसा मुझे भरोसा है। ■

कार्यालय के पास ही तीन सुंदर बागीचों का निर्माण दिल्ली नगर निगम और केंद्र सरकार मिल कर रही है। राशि वन, नक्षत्र वन, सप्तर्षि वन, तीर्थंकर वन के नाम से भव्य उपवन बनाए गए हैं, जो देखने लायक है। इस कार्यालय में 19 विभाग और 11 प्रकल्प होंगे, जो पार्टी को जनता के साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे।

करो अपने आप से स्पर्धा: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 16 फरवरी को परीक्षा संबंधी विषयों पर छात्रों के साथ एक 'टाउन हॉल' सत्र में बातचीत की। उन्होंने दिल्ली स्थित तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में छात्रों के प्रश्नों के जवाब दिये। छात्रों ने विभिन्न टेलीविजन समाचार चैनलों, नरेन्द्र मोदी मोबाइल एप और माय-गव प्लेटफार्म के जरिये उनसे सवाल पूछे।

संवाद की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वे छात्रों, उनके माता-पिता और उनके परिवार का मित्र होने के नाते 'टाउन हॉल' सत्र में आए हैं। उन्होंने कहा कि वे विभिन्न मंचों के जरिये देशभर के 10 करोड़ लोगों से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने अपने अध्यापकों को याद करते हुए कहा कि उनके अध्यापकों ने उनमें ऐसे मूल्यों का निरूपण किया, जिससे उनके भीतर का छात्र आज भी जीवित है। उन्होंने सबका आह्वान किया कि वे अपने अंदर के छात्र को जीवित रखें।

प्रधानमंत्री ने 'प्रतिस्पर्धा' (दूसरों के साथ स्पर्धा) के बजाय 'अनुस्पर्धा' (अपने आप से स्पर्धा) के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने द्वारा किए गए पिछले कार्य से बेहतर काम करना चाहिए।

उन्होंने आत्मविश्वास के महत्व को रेखांकित करने तथा परीक्षा के दबाव और चिंता के मद्देनजर स्वामी विवेकानंद का उदाहरण दिया। उन्होंने कनाडा के स्नोबोर्डर मार्क मैकमॉरिस का उदाहरण देते हुए कहा कि 11 महीने पूर्व उन्हें घातक चोट लगी थी और उनका जीवन खतरे में पड़ गया था, जिसके बावजूद उन्होंने शीतकालीन ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता।

एकाग्रता के विषय में प्रधानमंत्री ने महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की सलाह को याद किया जिसका जिक्र रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' में किया गया था। तेंदुलकर ने कहा था कि खेलते समय वे केवल उसी गेंद पर विचार करते थे, जो सामने होती थी। पिछली और अगली गेंदों के बारे में नहीं सोचते थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग से एकाग्रता में सुधार होता है।

हर माता-पिता बच्चों के लिए कुर्बानी देते हैं। इसका उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने माता-पिता से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों की उपलब्धियों को सामाजिक प्रतिष्ठा का मुद्दा न बनाएं। उन्होंने कहा कि हर बच्चे के पास कोई न कोई अनोखी प्रतिभा होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आईक्यू (बौद्धिक कौशल) और ईक्यू (भावनात्मक कौशल), दोनों का छात्र जीवन में बहुत महत्व होता है।

समय के समायोजन के संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों के लिए पूरे साल की कोई समय सारणी या कोई टाइम-टेबल व्यावहारिक नहीं होता। आवश्यकता है कि लचीला रुख अपनाते हुए समय का पूरा उपयोग किया जाए।

गौरतलब है कि 2 घंटे चले इस आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई तरह के सवालों के जवाब दिए, जिनमें घबराहट, चिंता, एकाग्रता, दबाव, माता-पिता की आकांक्षा और अध्यापकों की भूमिका जैसे प्रश्न शामिल थे। उन्होंने अपने उत्तर में हाजिर जवाबी के साथ तरह-तरह के उदाहरण दिए। ■

'किसानों की आय दोगुनी करने' पर राष्ट्रीय सम्मेलन

अब तक 20 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर सूक्ष्म सिंचाई उपलब्धः प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 20 फरवरी को दिल्ली के पूसा स्थित एनएएससी परिसर में 'कृषि-2022ः किसानों की आय दोगुनी करने' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में शिरकत की। यहां पर सात विषयगत समूहों ने निम्नलिखित विषयों पर प्रस्तुतियां दीं:

- नीति एवं गवर्नेंस संबंधी सुधार
- कृषि व्यापार नीति एवं निर्यात संवर्धन, बाजार की संरचना और विपणन दक्षता
- मूल्य श्रृंखला और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और कृषि क्षेत्र में स्टार्ट-अप
- सतत एवं न्यायसंगत विकास और सेवाओं को दक्षतापूर्वक उपलब्ध कराना
- पूंजीगत निवेश और किसानों के लिए संस्थागत ऋण
- पशुधन, डेयरी, पोल्ट्री और मत्स्य पालन को विकास के इंजनों के रूप में बढ़ावा देना

प्रधानमंत्री ने इन प्रस्तुतियों की सराहना की। उन्होंने विशेषकर दाल उत्पादन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी के लिए देश के किसानों की भी भूरि-भूरि सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए अनगिनत समन्वित कदम उठा रही है। इस संदर्भ में उन्होंने इन चार पहलुओं का उल्लेख कियाः कच्चे माल की लागत घटाना, उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना, उपज की बर्बादी रोकना और आमदनी के वैकल्पिक स्रोत सृजित करना।

सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए अनगिनत समन्वित कदम उठा रही है। इस संदर्भ में उन्होंने इन चार पहलुओं का उल्लेख कियाः कच्चे माल की लागत घटाना, उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना, उपज की बर्बादी रोकना और आमदनी के वैकल्पिक स्रोत सृजित करना।

श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि केन्द्र सरकार 99 अपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि इनमें से 50 सिंचाई परियोजनाओं के इसी वर्ष पूरा हो जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक सिंचाई परियोजना के पूरा हो जाने पर किसानों की कच्चे माल संबंधी लागत घट जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जरिए अब तक 20 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सूक्ष्म सिंचाई के दायरे में लाया गया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यूरिया की शत-प्रतिशत नीम कोटिंग से स्वयं यूरिया की भी क्षमता बढ़ गई है और इसके साथ ही उत्पादकता में भी वृद्धि दर्ज की जा रही है। उन्होंने कहा कि एक अध्ययन से यह संकेत मिला है कि मृदा स्वास्थ्य कार्डों के उपयोग से जहां एक ओर रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी आई है, वहीं दूसरी ओर उत्पादन बढ़ रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष बजट में घोषित 'ऑपरेशन ग्रीन्स' से टमाटर, प्याज और आलू उगाने वाले किसान लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि उपर्युक्त बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के साथ 22,000 ग्रामीण हाटों को उन्नत बनाया जाएगा और उन्हें ई-नाम प्लेटफॉर्म से एकीकृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी भूमि से 5 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर के दायरे में बाजारों से खुद को जोड़ने की सुविधा मिलेगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि ऋण के लिए मंजूर की गई धनराशि बढ़ा दी गई है, ताकि किसानों को आसानी से ऋण मिल सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि अपशिष्ट को संपदा में तब्दील करने के लिए अनेक पहल की जा रही हैं। ■

नीति आयोग के बजट आवंटन में 20 प्रतिशत की वृद्धि

वित्त मंत्री द्वारा नए भारत के लिए प्रस्तुत बजट से देश में परिवर्तन के वाहक के रूप में नीति आयोग की भूमिका मज़बूत हुई है। योजना राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री राव इंद्रजीत सिंह ने 21 फरवरी को यह बात कही। उन्होंने नीति आयोग के लिए बजट आवंटनों, नीति आयोग की उपलब्धियों तथा कार्यक्रमों की जानकारी भी दी। गौरतलब है कि योजना मंत्रालय, जो नीति आयोग का हिस्सा है, के लिए आवंटन 2017-18 के 279.79 करोड़ रुपये से 20 प्रतिशत से अधिक बढ़ाकर 2018-19 के लिए 339.65 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

साथ ही, इस बजट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कृषि नीति जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए नीति आयोग की भूमिका परिभाषित की गई है। इसके अलावा, नीति आयोग के तीन वर्षीय कार्य एजेंडा, सात वर्षीय कार्यनीति और 15 वर्षीय दृष्टि-पत्र के अनुरुप राष्ट्रीय विकास में साझा दृष्टिकोण को भी दोहराया गया है।

बजट में नीति आयोग

नीति आयोग केंद्र और राज्य सरकारों के परामर्श से एक विश्वसनीय व्यवस्था करेगा, ताकि किसानों को उनके उत्पाद के लिए उचित मूल्य मिल सके।

नीति आयोग राज्य सरकारों के परामर्श से एक उपयुक्त व्यवस्था ईज़ाद करेगा, ताकि पट्टेदारों को ऋण भी मिले और भू-स्वामियों के अधिकार भी सुरक्षित रहें।

नीति आयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसके अनुसंधान और अनुप्रयोग के क्षेत्र में हमारे प्रयासों को दिशा देने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरु करेगा।

ऊपर उल्लिखित के अलावा, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना- आयुष्मान भारत की आयोजना में नीति आयोग के अधिकारियों, सलाहकारों और नीति निर्माण की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रही है।

नीति आयोग: बीते से सबक, भविष्य पर नज़र

नीति आयोग ने अपने प्रारम्भ से ही भारत के नीतिगत मामलों में अच्छी पैठ बनाई है। नीति आयोग ने अपनी महत्वाकांक्षी सिफारिशों और सशक्त पहलों के ज़रिए निम्नांकित क्षेत्रों में सरकार के एक थिंक-टैंक के रूप में अपनी विशेषज्ञता प्रकट की हैः

- भारतीय कृषि के पुनरुज्जीवन और किसानों की आय दोगुनी करने की रूपरेखा तैयार करना

- अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए निश्चित निधि के अंतरण हेतु नए दिशानिर्देश तैयार करना
- राष्ट्रीय ऊर्जा नीति
- राष्ट्रीय पोषण कार्यनीति
- राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद विधेयक
- राष्ट्रीय चिकित्सा कार्यनीति
- केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कार्यनीतिक विनिवेश संबंधी सिफारिशें
- आदर्श भूमि पट्टाकरण विधेयक का निर्माण
- पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास स्कीम (एनईआईडीएस), 2017 के माध्यम से पूर्वोत्तर को विकास सहायता
- रोज़गार कार्यदल
- 12वीं पंचवर्षीय योजना का मूल्यांकन
- साझा और संयोजित गतिशीलता के लिए नीति तैयार करना
- द्वीपों का समग्र विकास

नीति आयोग विभिन्न कार्यक्रमों और स्कीमों के माध्यम से कार्य-स्थल (ऑन-ग्राउंड) पर प्रत्यक्ष नीतिगत हस्तक्षेप भी करता है। इनमें से कुछ निम्नानुसार हैं।

1. अटल नवप्रवर्तन मिशनः

- अटल नवप्रवर्तन मिशन नीति आयोग का एक अत्यन्त लोकप्रिय कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य देशभर के विद्यालयों में अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं और अटल इनक्यूबेशन केंद्रों के माध्यम से नवप्रवर्तन को बढ़ावा देना है। अटल महाचुनौती तथा टिंकरिंट मैराथन के आयोजनों से देशभर के युवा उद्यमियों को सीखने,

कुछ नया ईज़ाद करने और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से जुड़ने के लिए प्रोत्साहन मिला है।

- अब तक 2441 अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला विद्यालयों का चयन किया गया हैः
- चरण-1 में, 2016 में आमंत्रित आवेदनों के आधार पर 941 विद्यालय चयनित।
- चरण-2 में, 2017 में आमंत्रित आवेदनों के आधार पर अटलजी के 93वें जन्मदिन पर यानी 25 दिसम्बर, 2017 को 1500 विद्यालय चयनित।
- प्रत्येक अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला की स्थापना लागत के तौर पर 10 लाख रुपये की एकमुश्त राशि और अधिकतम 5 वर्षों के लिए 10 लाख रुपये के प्रचालन व्यय सहित अनुदान सहायता।
- अब अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं सभी राज्यों में मौजूद हैं।

इन्क्यूबेशन केंद्रः

- स्थापित इन्क्यूबेशन केंद्रः 2016-17 में 6 इन्क्यूबेशन केंद्र (ईआईसी) को सहायता दी गई। 2017-18 के दौरान लगभग 8-10 ईआईसी अनुमोदनाधीन हैं।
- ईआईसी के प्रचालन में तेज़ी लाने के लिए 10 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता किश्तों में दी जानी है।
- अटल इन्क्यूबेशन केंद्रः 2016-17 में 13 चयनित। 2017-18 के दौरान लगभग 20-25 विचारार्थ। अधिकतम 5 वर्षों के लिए 10 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता।

2. सहयोगपूर्ण संघवाद

- महत्वपूर्ण विषयों पर मुख्यमंत्रियों के उप-समूह (अप्रैल,2017)ः
- केंद्र-प्रायोजित योजनाओं का पुनर्गठन
- कौशल विकास
- स्वच्छ भारत
- डिजिटल भुगतानों को बढ़ावा
- सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और वित्त सचिवों के साथ राष्ट्रीय परामर्श
- आकांक्षी ज़िलों में बदलाव के कार्यक्रम के लिए देशभर के 115 ज़िलों के ज़िलाधिकारियों तथा प्रभारी अधिकारियों का सहयोग लेना
- सचिव समूहों द्वारा नीति आयोग को अभ्यावेदन देकर विभिन्न मंत्रालयों के बीच चर्चा और सहयोग

3. प्रतिस्पर्धी संघवाद

- राज्यों की रैंकिंग के लिए डिजिटल परिवर्तन सूचकांक तथा नवप्रवर्तन सूचकांक की शुरुआत।
- स्वास्थ्य सूचकांक की शुरुआत जो स्वास्थ्य परिणामों के मूल्यांकन के लिए वर्ष में एक बार देशभर में किया जाएगा।
- सूचकांकों के संबंध में, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए व्यापक कार्यशालाएं आयोजित।
- मानव पूंजी परिवर्तन हेतु संधारणीय कार्रवाई (साथ)ः स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में मुख्य संकेतकों के विकास हेतु राज्यों का मार्गदर्शन।
- विद्यालय शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक (एसईक्यूआई), समेकित जल प्रबंधन सूचकांक।

4. संधारणीय विकास लक्ष्य

- एसडीजी के कार्यान्वयन पर नज़र रखने वाले नोडल निकाय के तौर पर नीति आयोग ने राज्यों की प्रगति के आकलन हेतु केपीआई तैयार की।
- माप्य संकेतकों के साथ लक्ष्यों को मापने का मसौदा।

5. अर्थव्यवस्था के 15 महत्वपूर्ण क्षेत्रकों का परिणाम आधारित मूल्यांकन और अनुवीक्षण

निम्नलिखित के द्वारा उत्पादन-परिणाम फ्रेमवर्क में गुणात्मक सुधार लाने हेतु कड़ी कार्रवाई

- संगत उत्पादनों और परिणामों को चिह्नित करना और उनकी समीक्षा करना
- अनुवीक्षण के लिए मात्रात्मक और परिमेय संकेतक
- कार्य-निष्पादन की निगरानी के लिए कार्यनीतिक परिणाम सत्यापन प्रक्रिया (एसओवीपी)

कार्यक्रम मूल्यांकन

- 12 कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया गया
- निम्नलिखित से संबंधित मूल्यांकन रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम
आरटीई
सुमेलित सर्व शिक्षा अभियान
पीएमएवाई (शहरी)

- विभिन्न राज्यों की सर्वश्रेष्ठ कार्य-पद्धतियों का संकलन, प्रेषण और अनुकरण।
- समावेशः नीति आयोग तथा ज्ञान एवं अनुसंधान भागीदारों और संस्थाओं के बीच सहयोग को संभव बना रहा है।

6. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारियांः

- नीति आयोग व्याख्यान मालाः विद्वानों द्वारा "शासन" पर अब तक 3 व्याख्यान आयोजित किए जा चुके हैं
- नीति आयोग-डीआरसी वार्ताः सहयोग बढ़ाने के लिए नीति आयोग में चीन प्रकोष्ठ गठित किया गया।
- वैश्विक उद्यमिता शिखर-सम्मेलन 2017ः 2500 शीर्ष उद्यमियों, निवेशकों और इकोसिस्टम प्लेयर्स के साथ अमरीका-भारत शिखर सम्मेलन
- चैम्पियंस ऑफ चेंजः 12 क्षेत्रकों में नीतिगत सुझावों के लिए स्टार्ट-अप्स और उद्योग के साथ माननीय प्रधानमंत्री के

हितधारक विचार-विमर्श में सहयोग दिया।

7. उन्नत प्रौद्योगिकियों का अंगीकरण

- नीति आयोग ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी, एआई और शासन में इसके प्रयोग संबंधी पोजीशन पेपर पर कार्य कर रहा है
- भूमि अभिलेखों, इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य अभिलेखों, आदि पर प्रायोगिक चलाने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्रों के साथ भागीदारी
- 'इंडियाचेन'–साझेदारीयुक्त, भारत–विशिष्ट ब्लॉकचेन अवसंरचना के लिए संकल्पना पत्र पर कार्य
- नीति आयोग के लिए एमआईएस डेटाबेस का कार्यान्वयन
- भारत में मध्यस्थता और प्रवर्तन संबंधी सम्मेलन
- सरकार की सर्वश्रेष्ठ कार्य-पद्धतियों के संबंध में नीति आयोग के लिए डिजिटल हब

8. अनुसंधान, अध्ययन और सहयोग

- 5 अनुसंधान अध्ययन पूरे किए गए
- 7 राष्ट्रीय संगोष्ठियां और 2 अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां अनुमोदित
- 10 नए अनुसंधान अध्ययन अनुमोदित और पहली किस्त जारी
- 9 अनुसंधान अध्ययनों के लिए दूसरी किस्त जारी

9. मध्यस्थता का सुदृढ़ीकरण और विधिक सुधार

- 'भारत में मध्यस्थता और प्रवर्तन का सुदृढ़ीकरण' विषय पर वैश्विक सम्मेलन
- भारत विधि आयोग के सहयोग से 'राष्ट्र के तीन स्कंधों की भूमिकाओं का संतुलन' विषय पर विधि दिवस सम्मेलन
- महामहिम राष्ट्रपति; लोक सभा अध्यक्ष; प्रधान मंत्री, अन्य मंत्रियों; उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, विधिक समुदाय और शिक्षाविदों सहित प्रतिदिन 1500 से अधिक सहभागियों की प्रतिभागिता।

गौरतलब है कि भारत सरकार के अग्रणी 'थिंक टैंक' के रूप में नीति आयोग आर्थिक क्षेत्र के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मामलों, देश की और अन्य देशों की सर्वश्रेष्ठ कार्य-पद्धतियों के प्रचार-प्रसार, नए नीतिगत विचारों के समावेशन और विशिष्ट मामलों में सहायता प्रदान करते हुए देश का मार्ग प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

'चार्जिंग दी ड्राइव' आयोजन

बिजली चालित वाहनों से प्रदूषण कम होने के साथ ही रोजगार बढ़ेगा: नितिन गडकरी

सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत बिजली से चलने वाले वाहनों के उपयोग में बढ़त बनाने को तैयार है। उन्होंने यह बात 15 फरवरी को नीति आयोग के परिसर में 'चार्जिंग दी ड्राइव' आयोजन का उद्‌घाटन करने के बाद कही।

श्री गडकरी ने कहा है कि नीति आयोग बिजली से चलने वाले वाहनों को प्रोत्साहन दे रहा है और यह एक ऐतिहासिक तथा क्रांतिकारी कदम है। उन्होंने कहा कि बिजली से चलने वाले वाहनों के इस्तेमाल से कच्चे तेल के आयात में कमी होगी और प्रदूषण को बड़े पैमाने पर कम करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा, 'आज का प्रयास अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, आयात का विकल्प देगा, प्रदूषण कम होगा और रोजगार बढ़ेगा।'

मंत्री महोदय ने सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में होने वाली प्रगति को बिजली से चलने वाले वाहनों की क्षमता से जोड़ते हुए उद्योग जगत से आग्रह किया कि वे 'मेक इन इंडिया' के हवाले से इस दिशा में काम करें। उन्होंने जन यातायात में बिजली के वाहनों के इस्तेमाल को प्रोत्साहन दिया और कहा कि जल्द धोलाकुंआ, दिल्ली से मानेसर के बीच 70 किलोमीटर लंबी इलेक्ट्रिक रोपवे प्रणाली बनाई जाएगी।

नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अमिताभ कांत ने इस अवसर पर घोषणा की कि नीति आयोग अगले 4 महीनों के दौरान अपने वाहन-बेड़े को बिजली से चलने वाले वाहनों में बदलेगा। उन्होंने कहा कि हम दो पहिया, तीन पहिया और बसों को शामिल करते हुए हर तरह के वाहनों को बिजली से चलने वाले वाहनों में बदलेंगे। उन्होंने कहा कि सड़क यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय, बिजली मंत्रालय और भारी उद्योग विभाग मिलकर प्रधानमंत्री के 'मेक इन इंडिया' दृष्टिकोण के अनुपालन में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देंगे।

नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी के सारस्वत ने कहा कि वाहनों में वैकल्पिक ईंधन के इस्तेमाल के जरिये ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कमी लाई जा सकती है। नीति आयोग में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के महानिदेशक, डीएमईओ और सलाहकार श्री अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि इस संबंध में भारत ने बहुत प्रगति की है।

पत्र-पत्रिकाओं से...

विकास के लिए

उत्तर प्रदेश में हुई 'इनवेस्टर्स समिट' समिट तरक्की की दिशा में पहला कदम हो सकती है। समिट के पहले ही दिन अभी तक जो ब्योरा मिला है और जो माहौल दिखाई दिया है, उससे एक बड़ी उम्मीद तो बंधती ही है। देश और दुनिया भर के बड़े उद्योगपतियों का एक साथ एक मंच पर पूरी तैयारी के साथ जमा होना, और एक के बाद एक 4.28 लाख करोड़ रुपये के 1,045 एमओयू पर दस्तखत होना यह बताता है कि यह सिर्फ राज्य सरकार का एक औपचारिक प्रयास भर नहीं है, बल्कि देश-दुनिया के उद्योगपति इसमें खासी दिलचस्पी ले रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश को एक नई चुनौती दी, प्रदेश को महाराष्ट्र से पहले ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने की चुनौती। महाराष्ट्र के लिए भी यह बहुत आसान नहीं है, पर वह इससे ज्यादा दूर भी नहीं है। उत्तर प्रदेश को इसके लिए काफी दूरी तय करनी होगी। उत्तर प्रदेश के मुकाबले महाराष्ट्र के पास बहुत बड़ा व विकसित इन्फ्रास्ट्रक्चर है। उत्तर प्रदेश अगर ऐसी तमाम दिक्कतों के बावजूद महाराष्ट्र को पछाड़ सका, तो एक इतिहास बन जाएगा। प्रदेश के पास इसकी क्षमता तो है, लेकिन चुनौती उस क्षमता के सही उपयोग की है। इसके लिए प्रदेश को उन सब बाधाओं को भी दूर करना होगा, जिसके कारण निवेशक पहले भी उत्तर प्रदेश आते-आते रह जाते थे।

— (हिन्दुस्तान, २३ फरवरी, २०१८)

निवेश की आस

लखनऊ में हुए दो दिवसीय निवेशक सम्मेलन में जो उत्साह देखा गया उससे उम्मीद पैदा हुई है ,गौरतलब है कि सम्मेलन में रिलायंस, अडाणी, आदित्य बिड़ला और टाटा समूह सहित देश के बड़े औद्योगिक घरानों ने उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए उत्साह दिखाया है। निश्चित रूप से यह राज्य सरकार के लिए खुश होने की बात होगी कि इस आयोजन में चार लाख अट्ठाईस हजार करोड़ रुपए के निवेश की घोषणाएं हुई। इतनी बड़ी राशि की अहमियत इसलिए भी है कि पहली बार किसी राज्य को अपने सालाना बजट यानी चार लाख अट्ठाईस हजार करोड़ रुपए के बराबर निवेश के प्रस्ताव मिलेदेखा गया है कि बहुत सारे एमओयू यानी सहमति-पत्र घोषित तो हो जाते हैं, पर कार्यान्वित नहीं हो पाते। सम्मेलन में जितनी बड़ी रकम के निवेश के प्रस्तावों पर सहमति की घोषणाएं हुई हैं, उन पर न केवल गंभीरता से अमल सुनिश्चित कराने की जरूरत है, बल्कि इसके साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों के ढांचे को भी मजबूत और कारगर बनाने पर शिद्दत से ध्यान देना होगा।

— (जनसत्ता, २३ फरवरी, २०१८)

यदि मुख्य सचिव ही सुरक्षित नहीं तो फिर कौन है?

राजनीति में कुछ भी संयोगवश नहीं होता, यदि यह होता है तो आप शर्त लगा सकते हैं कि इसकी योजना ही उस तरह बनाई गई थी।' एक कोट में यह कहा गया है, जो व्यापक रूप से रूजवेल्ट का बताया जाता है। दिल्ली में 20 फरवरी की रात जो पटकथा सामने आई वह सुनियोजित प्रतीत होती है। लगता है मुख्य सचिव अंशु प्रकाश को जाल बिछाकर मुख्यमंत्री निवास पर बुलाया गया, ऐसी जगह जहां जाने से वे इनकार नहीं कर सकते थे। अपने ही विधायकों के दबाव में मुख्यमंत्री ने उनका सीधे सामना करने के लिए मुख्य सचिव को बुला लिया। लेकिन, इसके बाद पटकथा गड़बड़ होकर मुख्य पात्र के काबू से बाहर चली गई। यदि केजरीवाल को मुख्य सचिव से वाकई कोई समस्या है तो कई लोकतांत्रिक व सभ्य तरीके उपलब्ध हैं, फिर चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में एक आईएएस अधिकारी को नियंत्रित करने की गुंजाइश कितनी ही कम क्यों न हो जब एलजी (उपराज्यपाल) दिल्ली विधानसभा में आएंगे तो क्या अब हम विधायकों से उनकी रक्षा के लिए पुलिस सुरक्षा मांगेंगे? तब हम क्या उत्तर कोरिया या म्यांमार से अलग हैं?

— (दैनिक भास्कर, २१ फरवरी, २०१८)

स्फुट विचार...

गरीबी–पिछड़ापन का एक बहुत बड़ा कारण है जनसंख्या। जनसंख्या की बहुलता और इसको रोकने के प्रयत्न में नागरिकों की जनजागरण की दिशा में हमें तेजी लानी होगी। जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति के कारण देश में अनेकानेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।

— कुशाभाऊ ठाकरे

कंधे-से-कंधा लगाकर, कदम-से-कदम मिलाकर हमें अपनी जीवन-यात्रा को ध्येय-सिद्धि के शिखर तक ले जाना है। भावी भारत हमारे प्रयत्नों और परिश्रम पर निर्भर करता है। हम अपना कर्तव्य पालन करें, हमारी सफलता सुनिश्चित है।

— अटल बिहारी वाजपेयी

प्रस्तुति: पंकज आनंद

SUBSCRIBE

KAMAL SANDESH

The Hon'ble Prime Minister SHRI NARENDRA MODI becomes Life Time Member of Kamal Sandesh

BECOME PART OF A VIBRANT IDEOLOGICAL MOVEMENT

SUBSCRIPTION DETAILS

Name : ....

Address : ....

....

.... Pin : ....

Phone : .... Mobile : (1).............................. (2)..............................

E-mail : ....

SUBSCRIPTION TYPE						
	One Year	₹350/-	☐	Life Time (English or Hindi)	₹3000/-	☐
	Three Years	₹1000/-	☐	Life Time (English+Hindi)	₹5000/-	☐

(DETAIL OF THE PAYMENT)

Cheque/Draft No. :.............................. Date :........................ Bank : ....

Note : * DD/Cheque will be made in favour of "**Kamal Sandesh**"

* Money order and Cash accepted with details

(Subscriber's Signature)

KAMAL SANDESH

SEND YOUR DD/CHEQUE ON THIS ADDRESS

Dr. Mookerji Smruti Nyas, PP-66, Subramania Bharati Marg, New Delhi-110003

Ph.: 011-23381428 **Fax:** 011-23387887 **E-mail:** kamalsandesh@yahoo.co.in

KAMAL SANDESH - DEDICATED TO NATIONAL CAUSE

फुलबारी (मेघालय) में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

इटानगर (अरुणालच प्रदेश) में स्थित दोरजी खांडू स्टेट कान्वेशन सेंटर का उद्‌घाटन करते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

लखनऊ में यूपी इंवेस्टर्स समिट, 2018 के उद्‌घाटन अवसर पर भाजपा वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में ईरान के राष्ट्रपति डॉ. हसन रुहानी से हाथ मिलाते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

मस्कत (ओमान) के एक कम्युनिटी इंवेट में जनाभिवादन स्वीकार करते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित

आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2018-20
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2018-20

समृद्ध किसान, प्रगतिशील राष्ट्र

- देश में 275 मिलियन टन से ज्यादा खाद्यान्न और लगभग 300 मिलियन टन फलों-सब्जियों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ
- eNAM पोर्टल पर अब तक 36 हजार करोड़ रुपए से अधिक की कृषि वस्तुओं का व्यापार किया गया
- दशकों से लंबित 99 सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का काम भी प्रगति पर है
- दालों और तेल के बीज पर दिया गया उत्पादन बोनस, उत्पादन में 38 प्रतिशत से अधिक की हुई बढ़ोतरी
- किसानों की उपज, बाजार तक पहुंचने से पहले क्षतिग्रस्त न हो, इस उद्देश्य से शुरू की गई 'प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना'
- 11 हजार करोड़ रुपए की 'डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि' की स्थापना की जा रही है
- यूरिया का उत्पादन बढ़ा, 100 प्रतिशत नीम कोटिंग के बाद यूरिया की कालाबाजारी रुकी

आधुनिक परिवहन व्यवस्था के माध्यम से कनेक्टिविटी को बढ़ावा

एयरवेज

- छोटे शहरों में हवाई संपर्क प्रदान करने के लिए 'उड़ान' योजना शुरू की गई
- 'उड़ान' योजना की शुरूआत के मात्र 15 महीनों में 56 हवाई अड्डों और 31 हेलीपैडों को जोड़ने के लिए कार्य शुरू किया गया
- 16 ऐसे हवाई अड्डों से उड़ानें शुरू भी हो चुकी हैं

सभी के लिए बेहतर एवं सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं

- गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य की बेहतर और सस्ती सुविधा के लिए नई 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति' तैयार की गई
- 'राष्ट्रीय आयुष मिशन' द्वारा योग-आयुर्वेद जैसी परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है
- 3,000 से अधिक 'प्रधानमंत्री जन औषधि' केन्द्रों के माध्यम से गरीबों को 800 तरह की दवाइयां सस्ती दरों पर दी जा रही हैं
- 'दीनदयाल अमृत योजना' के तहत 111 आउटलेट के माध्यम से 5,200 से अधिक लाइफ सेविंग ब्रांडेड दवाओं तथा सर्जिकल इम्प्लांट्स पर 60 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक की रियायत दी जा रही है

कमजोर वर्ग हो रहा है सशक्त

- 'राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग' को संवैधानिक दर्जा देने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया
- आदिवासियों द्वारा एकत्र किए जाने वाले कई वन उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया गया
- बांस को पेड़ की श्रेणी से हटाया गया, अब बांस को काटने, उसके परिवहन और उपयोग की स्वतंत्रता मिली
- स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समुदायों के बहुमूल्य योगदान का सम्मान करने के लिए देश में आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना की जा रही है